● वर्ष-4
● अंक-95
रायपुर, शुक्रवार
29 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» लगातार बनी रहती है थकान तो ऐसे...

पद्मश्री विभूतियों की सम्मान राशि प्रतिमाह 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने की घोषणा

प्रदेश में 147 करोड़ की लागत से बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 147 करोड़ रूपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए भारत सरकार ने 147 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए गए अपने सम्बोधन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा फिल्म सिटी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण से छत्तीसगढ़ी फिल्मों, छत्तीसगढ़ी नाटकों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मान से विभूषित छत्तीसगढ़ की विभूतियों को दी जाने वाली सम्मान राशि प्रतिमाह 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा है, जो हमें आपस में दिल से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्में काफी लोकप्रिय हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने में छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भी बड़ा योगदान है।

मुख्यमंत्री ने साहित्य परिषद में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के विलय की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग राजभाषा छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने का कार्य करता रहेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का साहित्य परिषद में विलय कर दिया गया था।

छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात

चित्रोत्पला फिल्म सिटी से छत्तीसगढ़ी फिल्मों, नाटकों के साथ पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने वाले छह साहित्यकारों को शॉल-श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को लोकप्रिय बनाने और राजभाषा का सम्मान देने के लिए यह जरूरी है कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा में बातचीत करें और नई पीढ़ी को भी छत्तीसगढ़ी बोलना सिखाए। उन्होंने साहित्यकारों से छत्तीसगढ़ी भाषा में उपन्यास, कविता और इतिहास का लेखन करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सदस्य छत्तीसगढ़ी में अपना सम्बोधन दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद के रूप में वे छत्तीसगढ़ी को संविधान की आठवें अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में पद्श्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे और डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की महिला सरपंच की बहाली का आदेश

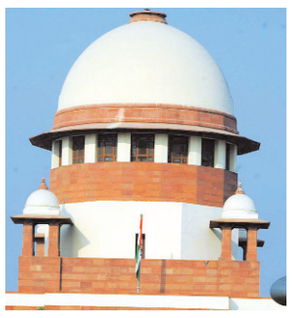

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ की महिला सरपंच की बहाली का आदेश जारी किया। कोर्ट ने आदेश में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अफसरों को ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। मौजूदा समय में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की सजबहार पंचायत की महिला सरपंच सोनम लकड़ा को निर्माण सामग्री की आपूर्ति और निर्माण कार्य पूरा होने में देरी पर सरपंच पद से हटा दिया गया था। सोनम ने राज्य के अधिकारियों के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सोनम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को याचिका पर सुनवाई की और अफसरों के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही महिला सरपंच को बहाल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने गुरुवार को बहाली आदेश जारी करते हुए लिखा कि प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर से एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि और एक लोक सेवक के बीच अंतर को समझने में फेल रहे हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अक्सर निर्देशों का पालन करने के लिए नौकरशाहों के अधीनस्थ माना जाता है। यह उनकी स्वायत्तता पर अतिक्रमण करने और उनकी जवाबदेही को प्रभावित करता है। प्रशासनिक अधिकारियों को महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व की पहल का समर्थन करना चाहिए।

महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की जरूरतः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्थिक महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहे एक राष्ट्र में ऐसी घटनाओं का लगातार होना और सामान्य हो जाना दुखद है। आदेश में कहा गया कि यह काफी चिंता करने वाली बात है कि बार-बार ऐसे मामले सामने आते हैं।

जहां प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम पंचायत सदस्य महिला सरपंचों के खिलाफ बदला लेने के लिए मिलीभगत करते हैं। ऐसे में आत्मनिरीक्षण और सुधार की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित पदों पर महिलाओं को हतोत्साहित करने की बजाय ऐसे माहौल को बढ़ावा देना चाहिए जो शासन में उनकी भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करे। पीठ ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर सरपंच को एक लाख रुपये का भुगतान करने और उसके उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दोषी अधिकारियों से लागत वसूलने की अनुमति दी।

लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन

कोर्ट ने उन अधिकारियों की मानसिकता पर भी सवाल उठाया जो चुने हुए प्रतिनिधियों को नौकरशाही का अधीनस्थ मानते हैं। कोर्ट ने कहा, चुनाव के माध्यम से मिले जनादेश को नौकरशाही के आदेशों के तहत लाना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज और प्रशासन से आत्मनिरीक्षण करने की अपील की।

पंचायत सदस्यों की मिलीभगत से सब कुछ हुआ

कोर्ट ने आदेश में कहा कि मामले की जांच से पता चला है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर महिला सरपंच की पहल में बाधा डालने की कोशिश की थी। ग्राम पंचायत सदस्यों ने कदाचार के निराधार आरोप लगाकर सरपंच की विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की।

चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत

रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई. हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी मां रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद रहीं। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित अन्य नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेम्ब्रोम को 39 हजार 791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी थी। जबकि झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटें हासिल कर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें मिलीं। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन में सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34 सीटें हासिल की थी।

स्टालिन का मोदी को पत्र, कहा- मदुरई जिले में दिए गए टंगस्टन खनन अधिकार को रद्द करें

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार रद्द करने का अनुरोध किया। साथ ही लोगों के डर को भी सामने रखा। मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार दिए जाने के केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए सीएम स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री से इसे रद्द करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार जैव-विविधता विरासत स्थल और लोगों के विरोध जैसे पहलुओं पर विचार करते हुए वहां खनन की अनुमति नहीं देगी। स्टालिन ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि अधिसूचित जैव-विविधता विरासत स्थल खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में से एक के अंतर्गत आता है और घनी आबादी वाले गांवों में वाणिज्यिक खनन निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करेगा, जिन्हें डर है कि उनकी आजीविका हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और इसलिए राज्य कभी भी खनन की अनुमति नहीं देगा।

प्रमुख समाचार

बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

हरिकोटा। भारतीय नौसेना ने के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का गुरूवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 3500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल हाल ही में इंडक्ट की गई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन (पनडुब्बी) से दागी गई है। बंगाल की खाड़ी में हुए इस परीक्षण को भारतीय डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इससे देश की न्यूक्लियर ताकत में इजाफा होगा। इस मिसाइल को पानी के भीतर से पनडुब्बी के जरिए दागा जा सकता है। इसके चलते दुश्मनों को हमले की भनक तक नहीं हो सकेगी। डिफेंस सोर्सेस ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि मिसाइल टेस्ट के रिजल्ट को अभी एनालाइज किया जा रहा है। इसके बाद टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ किया जाएगा। यह परीक्षण भारत की परमाणु त्रिकोण को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे परमाणु हमले की स्थिति में देश की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता सुनिश्चित होगी। पानी के नीचे से लॉन्च किए जाने के लिए डिजाइन की गई के-4 बैलिस्टिक मिसाइल भारत के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहले मिसाइल को इसके पूर्ण-सीमा परीक्षण के लिए तैयार करने के लिए व्यापक परीक्षण किए थे.

पंजाब सरकार पर भड़का सुको- अफसर किसानों को दे रहे दिमाग

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में पलूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि ग्रैप-4 की पाबंदियां 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी और उस दिन सुनवाई में फैसला लिया जाएगा, इसे आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जारी रखने की बात कही है और कहा कि यह गंभीर मसला है। इसलिए हम इस पर सुनवाई करते रहेंगे। यही नहीं बेंच ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि राज्य के अधिकारी किसानों को कह रहे हैं कि वे शाम को 4 बजे के बाद पराली जलाएं। ऐसा करने से वे सैटेलाइट की नजर में नहीं आएंगे। बेंच ने कहा कि ऐसा करना गलत है और अदालत के आदेश की अवमानना है। अदालत ने कहा कि हमें पलूशन से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान ही निकालना होगा। बेंच ने कहा, पंजाब सरकार अपने अधिकारियों को आदेश दे कि वे किसानों को ऐसी सलाह न दें कि 4 बजे के बाद पराली जलाई जा सकती है। ऐसा करना आदेश का उल्लंघन है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदेश का पालन करें। इसकी बजाय यदि वे पराली जलाने के लिए किसानों को दिमाग दे रहे हैं.

डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन को लेकर पन्नू ने दी धमकी

नई दिल्ली। भुवनेश्वर में ओडिशा डीजीपी सम्मेलन से एक दिन पहले, खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने गुरुवार को एक संदेश जारी कर अखिल भारतीय बैठक को बाधित करने की धमकी दी, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन के प्रमुख पन्नू ने एक वीडियो संदेश में अपने समर्थकों से डीजी-आईजी सम्मेलन को बाधित करने के लिए भुवनेश्वर के मंदिरों-होटलों में भेष बदलने और छिपने का आग्रह किया। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक नामित आतंकवादी, पन्नून ने प्रधानमंत्री को भक्तों से मिलने के लिए भुवनेश्वर में राम मंदिर जाने की चुनौती दी और नक्सलियों, माओवादियों, कश्मीरी लड़ाकों से डीजी-आईजी सम्मेलन को बाधित करने के लिए भुवनेश्वर के मंदिरों, होटलों में भेष बदलने और छिपने का आग्रह किया। यह कहते हुए कि एनआईए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी, आईबी और सीआईएसएफ के 200 से अधिक सुरक्षा अधिकारी शाह के नेतृत्व में मिलेंगे, पन्नून ने कहा कि बैठक में खालिस्तानी समर्थक सिखों, कश्मीरी लड़ाकों, नक्सलियों और माओवादियों की हत्या की योजना बनाई जाएगी और योजना बनाई जाएगी।

वहां तो पीएम भी हर साल चादर भेजते हैं: ओवैसी

नई दिल्ली। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हुए हालिया विवाद के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा। इससे पहले, राजस्थान की एक अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह को भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करने वाली हिंदू सेना की याचिका स्वीकार कर ली थी। उसी पर बोलते हुए, ओवैसी ने दरगाह के इतिहास पर प्रकाश डाला और कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर पिछले प्रधानमंत्रियों ने दरगाह पर चादरें भेजी हैं। विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि यह दरगाह पिछले 800 वर्षों से वहां मौजूद है। उस समय मुगलों का शासन था। बादशाह अकबर ने वहां बहुत सी चीजें बनवाईं। फिर मराठों का शासन आया बाद में अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया गया। 1911 में जब महारानी एलिज़ाबेथ वहां आईं तो उन्होंने वहां एक जलघर बनवाया। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर कई प्रधान मंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। बीजेपी-आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर ये नफरत क्यों फैलाई है?

मणिपुर हिंसाः निकाल ली आंखें, सिर काटा... 6 लोगों की हत्या की रिपोर्ट

इंफाल। मणिपुर की धरती इन दिनों मानवता के सबसे काले अध्यायों में से एक को लिख रही है। जिरीबाम जिले में एक ही परिवार के छह निर्दोष सदस्यों की हत्या ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आई जानकारी इतनी भयावह है कि इसे सुनकर रूह कांप उठती है। मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, किसी को भी इस क्रूरता में नहीं बख्शा गया। गोली के निशान, शरीर पर गहरे जख्म, और सबसे दर्दनाक, आंखों का गायब होना - ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो मानवता को शर्मसार करती हैं। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक क्रूरतापूर्ण अत्याचार था, जो मानवीय मूल्यों को पूरी तरह से तार-तार कर देता है। यह परिवार मेइती समुदाय का बताया जा रहा है और आरोप है कि कुकी उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई ऑटोप्सी के मुताबिक, 10 महीने के लैशराम लमंगनबा के शरीर पर काटने का घाव था, सिर अलग था और दोनों आंखें गायब थीं। 17 नवंबर को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ के बाद संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर के जिरीबाम जिले के बोरोबेकरा इलाके से तीन महिलाओं और तीन बच्चों का अपहरण कर लिया था।

एक किताब ने खोला दरगाह में मंदिर होने का राज!

नई दिल्ली। सूफी इस्लाम को मानने वाले राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक मानते हैं यहां मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, जहां हर धर्म के लोग जियारत और अकीदत पेश करने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा कहां से आए थे और इस दरगाह का इतिहास क्या है?

अजमेर पर लिखी गई एक किताब का जिक्र करते हैं, जो यहां के हिस्टोरिकल फैक्ट को बताती है। इसके चैप्टर 8 के पेज 82 से 89 तक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया गया है। इसी पुस्तक में दरगाह की जगह एक मंदिर होने की बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की भी बात लिखी गई है। ये किताब हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से न्यायाधीश मनमोहन चंदेल के समक्ष पेश की गई है।

क्या लिखा है किताब में?- दरअसल, किताब में इस बात का जिक्र है कि यहां ब्राह्मण दंपती रहते थे। वे दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं, जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहां शिव मंदिर रहा था।

दरअसल, इस किताब के लेखक का नाम हरबिलास शारदा है। हरबिलास शारदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवा अजमेर मेरवाड़ा (1892) के न्यायिक विभाग में भी रहकर दी है। बड़ी बात ये है कि अजमेर में उनके नाम से हरबिलास शारदा मार्ग भी है। इन्होंने ही 1911 में इस किताब को लिखा था।

क्या है दरगाह का इतिहास?- ऐसा माना जाता है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। उन्हें लोग ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारते हैं। वो एक फारसी इस्लामिक स्कॉलर थे। जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान

के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, वो अपने मानवता के उपदेशों की वजह से काफी मशहूर हुए। यही वजह है कि हर धर्म के लोग उन्हें पसंद करते थे। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया और मृत्यु तक वो यहीं रहे ।

किसने कराया दरगाह का निर्माण?- जानकारी के मुताबिक सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था।दरगाह के अंदर विशाल चांदी के दरवाजों की एक श्रृंखला के जरिए प्रवेश किया जा सकता है। यहां संत की कब्र मौजूद है। संगमरमर और सोने की परत से बना, वास्तविक मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर के पत्थरों से सुरक्षित है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थयात्रा करते थे। उन्होंने और बादशाह शाहजहां ने दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाईं। अकबर की जियारत का सीन मशहूर फिल्म जोधा-अकबरमें फिल्माया गया है। 1568 और 1614 में मुगल राजा अकबर और जहांगीर ने विशाल डेग दान में दी थीं। जो अभी भी यहां पर हैं। ये दोनों डेगों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसमें चावल, घी, काजू, बादाम, चीनी और किशमिश की मदद से लंगर तैयार किया जाता है।

बादशाह अकबर पैदल आए थे दरगाह - अजमेर मे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है। लोग यहां अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहिब का शुक्राना अदा करने आते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किमी. पैदल ही चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह मे पुत्र प्राप्ति की कामना लिए आया था।

सभी धर्मों के आते हैं लोग - अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। यहां अक्सर बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों की सफलता के लिए दुआ मांगने आते रहे हैं। दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अदभुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है, यहां आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गत नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े-बड़े राजनेता एवं सेलिब्रिटीज आते रहते हैं और अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं।

फारस से आए थे भारत - ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज यात्रा की थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच में वे फारस से भारत यात्रा पर आए थे.

अटल विवि में आयोजित जनजातीय गौरव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के संरक्षक : राज्यपाल मंगू भाई

बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित जनजातीय गौरव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समुदाय की महत्ता और उनके योगदान को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे जनजातीय विकास कार्यों की सराहना की। कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षक है। जनजातीय गौरव को बढ़ावा देने के कार्यक्रम राज्यपाल पटेल ने कहा कि आज देशभर में जनजातीय गौरव को बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समाज जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षक रहे हैं और उनकी जीवनशैली से पर्यावरण संरक्षण के मूल सिद्धांत सीखे जा सकते हैं। उन्होंने जनजातीय समुदायों की परंपराओं और उनके योगदान को संरक्षित और संवर्धित करने के प्रयासों को जरूरी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने की। जनजाति गौरव

संगोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्लवन के साथ एवं राष्ट्रगान एवं कुल गीत के साथ शुरुआत हुई। संगोष्ठी में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रामलाल रौतेल, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश एवं विशेष अतिथि के रूप में विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और जनजाति गौरव के प्रांत संयोजक बृजेंद्र शुक्ला,कुलसचिव शैलेंद्र दुबे उपस्थित थे।

आदिवासियों में सिकल सेल एक बड़ी समस्या राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों में सिकल सेल एक बड़ी समस्या है। हमको जांच करना चाहिए और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो काम शुरू किया है उन्होंने 15000 करोड रुपए का बजट में प्रावधान किया है। मां-बाप को होगा तो बच्चे को समस्या आएगी उन्होंने इस बीमारी से होने सभी लक्षणों को चर्चा की। यहां छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा कि सरकार इस भीषण मे लगातार काम कर रही है।

अटल विश्वविद्यालय ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित सात आदिवासी समाज की विभूतियों को जनजातीय गौरव सम्मान से विभूषित किया। कुलपति वाजपेयी ने उन्हें यह सम्मान दिया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, मध्यप्रदेश कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, मधुलिका सिंह, उत्कृष्ट पुलिसिंग, डा.चंद्रशेखर ऊइके चिकित्सा सेवा, डा. ज्योति रानी सिंह शिक्षा और इतवारी सिंह राज को क्रीड़ा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया।

आर्थिक संकट से जूझ रहा है निगम, 5 माह से नहीं मिला वेतन

11 दिसंबर से काम बंद की चेतावनी

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चिरमिरी नगर निगम इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जिसका असर यहां काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। हालात ये है कि पिछले पांच महीनों से निगम के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। दशहरा और दिवाली जैसे पर्व में भी इन कर्मचारियों के घरों में खुशी के दिए नहीं जले।फिर भी ये मन लगाकर अपने काम में डटे रहे।लेकिन अब तो हालात ये हैं कि किसी दूसरे से पैसे मांगने की सूरत भी नहीं बची।

पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने कर्मचारियों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से बातचीत की।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मचारियों के वेतन में पहले एक-दो महीने की देरी होती थी।जिसे लोग किसी तरह सहन कर लेते थे। लेकिन अब पांच महीने से वेतन नहीं मिलने से हालात बहुत खराब हो गए हैं।

डॉ विनय जायसवाल ने कहा निगम के गरीब कर्मचारियों के हित में तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। कर्मचारी दाने-दाने को मोहताज हो गए हैं। वे अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करें ? त्योहारों में जब हर घर खुशियों से भरा हुआ था, ये कर्मचारी सब्जी और राशन तक के लिए संघर्ष कर रहे थे।नगर निगम के कर्मचारी बेहद कठिन परिस्थितियों में हैं।उनकी समस्या को लेकर मैंने कलेक्टर से बात की है।उम्मीद है कि जल्द ही समाधान निकलेगा।

नगर निगम कर्मचारियों का वेतन अटकने के पीछे क्या कारण हैं, इसका अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। विनय जायसवाल ने कहा कि प्रशासन को इसे प्राथमिकता से हल करना चाहिए। भविष्य में इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली में भी वेतन नहीं मिला।ऐसा लगातार हो रहा है कि कभी 2 महीने में वेतन मिलता है,तो कभी चार महीने में वेतन मिलता है।कभी भी समय में हम लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है।वहीं क्रमोन्नति में कर्मचारियों को कई सालों तक इंतजार करना पड़ रहा है।इसका समाधान नहीं होने पर हम विरोध करेंगे। निगम कर्मचारी विकास पाण्डेय ने कहा आगामी 11 दिसंबर से हम सभी हड़ताल पर जाएंगे।समस्त कर्मचारी और संघ ने ये फैसला किया है कि हम निगम के कार्यों को बंद करेंगे।चाहे वो सफाई व्यवस्था हो,पानी की व्यवस्था हो या निर्माण कार्य हो।

आपको बता दें कि निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। नगर निगम के कर्मचारियों को अब प्रशासन से उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उनकी जिंदगी सामान्य हो सके।

भिलाई चरोदा में डायरिया का प्रकोप

18 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत, स्वास्थ्य विभाग की टीम डटी

भिलाई। भिलाई चरोदा के आदर्श नगर में 18 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित पाए गए हैं। जिसमें चार लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं 14 लोगों का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि भिलाई चरोदा आदर्श नगर के वार्ड नंबर 23 में अचानक कुछ लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई।जिसके बाद सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे।इनमें से चार की हालत गंभीर थी।जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।वहीं अन्य 14 लोगों को दवाईयां देकर घर में रहने की हिदायत दी गई है।

भिलाई-चरोदा के वार्ड-23 की आबादी करीब 4000 है। यहां लगभग 900 मकान हैं। इसमें हाउसिंग बोर्ड का क्षेत्र भी शामिल है। जिस वार्ड के लोग पीड़ित हुए वहां दो अलग-अलग संपवेल से पानी की आपूर्ति की जाती है। वार्ड में करीब 50 घरों में जल आवर्धन योजना का पानी भी पहुंचता है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी ने कहा कि डायरिया की सूचना मिलते ही

स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम, चरोदा-भिलाई 3 की संयुक्त टीम ने डोर टू डोर सर्वेक्षण किया है।

जिला चिकित्सा अधिकारी मनोज दानी ने कहा उल्टी दस्त के मरीजों को ओआरएस और जिंक टेबलेट, मैटोजिल टेबलेट बांटे गए हैं। टीम ने लोगों को पानी उबालकर ठंडा करके पीने और ताजा भोजन करने की सलाह दी है। वहीं खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना बताया गया। निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 6 घरों से पानी का सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए भेजा है।वहीं चार गंभीर मरीजों का इलाज जारी है।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को पानी उबाल कर और ठंडा करके पीने और ताजा भोजन करने की सलाह दी है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों की साफ सफाई करें। इलाके में नगर निगम की टीम लगातार नालियों की साफ सफाई कर रही है। 6 घरों से पानी का सैंपल भी लिया गया है। फिलहाल लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत क्यों हुई ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल उल्टी दस्त से पीड़ित सभी लोगों की स्थिति अभी बेहतर बताई जा रही है।

माओवाद प्रभावित ग्रामों को शासन की योजनाओं से जोड़ने अनूठी पहल

■ संवेदनशील ग्रामों में भी अब उपलब्ध हो रहा शुद्ध पेयजल

कांकेर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के संवेदनशील एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए नियद नेल्लानार योजना लागू की है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की पहुंच चयनित गांवों में सुनिश्चित की जा रही है। योजनांतर्गत जिले के कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के क्लस्टर ग्राम पानीडोबीर सहित 07 गांवों में जिला प्रशासन द्वारा सतत् विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। शत-प्रतिशत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने लगातार कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत सड़क सम्पर्क, पुल-पुलिया निर्माण, आधार एवं राशन कार्ड बनाने, वन अधिकार पट्टा देने सहित स्वास्थ्य, विद्युत और पेयजल जैसी अनेक आवश्यक सेवाओं व सुविधाओं को सुलभ एवं सुचारू बनाने के भगीरथ प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं।

नियद नेल्लानार योजना के तहत चयनित ग्राम पानीडोबीर सहित आलपरस, हेटारकसा, गुन्दूल, अलपर, जुगड़ा और चिलपरस के ग्रामीणों को जलजीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से क्रेडा द्वारा सोलर (सौर उर्जा) आधारित ड्यूल पंपों की स्थापना की गई है। सहायक अभियंता क्रेडा ने बताया कि जलजीवन मिशन के तहत नल-जल योजना से जिले के नियद नेल्लानार योजनांतर्गत चिन्हांकित 07 गांवों में 14 नग सोलर आधारित ड्यूल पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि चयनित ग्राम पानीडोबीर में 01 नग, आलपरस में 03, हेटारकसा में 02, गुन्दूल और मर्रांम में 02, अलपर में 01, जुगड़ा में 02 तथा ग्राम चिलपरस में 03 नग, इस प्रकार कुल 14 सोलर आधारित ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य क्रेडा द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में कुएं और हैण्डपंप से पानी भरना पड़ता था, जिसमें अतिरिक्त मेहनत के साथ ही काफी समय भी लगता था। वहीं गर्मी के दिनों में भूजल स्तर में गिरावट आ जाने से गांव के अधिकांश कुएं सूख जाते थे और पानी की शुद्धता भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी। सोलर आधारित ड्यूल पंपों की स्थापना के बाद अब हर घर नल-जल कनेक्शन से ग्रामवासियों के प्रत्येक घर में स्वच्छ और शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो रही है। इससे ग्रामीणों में शासन की योजनाओं के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है, साथ ही दैनिक जीवन में आशातीत व सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। नियद नेल्लानार योजना से इन गांवों में अब विकास की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है।

इंजिनियरिंग की पढ़ाई कर एकलव्य साहू ने किया खेती-किसानी का रूख

धमतरी। आजकल जहां युवा पीढ़ी पढ़-लिखकर विभिन्न नौकरियों की ओर अग्रसर हो रही है, वहीं जिले के मगरलोड विकासखण्ड स्थित ग्राम दुधवारा के युवा एकलव्य साहू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर खेती-किसानी की ओर रूख किया। शिक्षित होने के साथ-साथ उन्हें खेती-किसानी की तकनीकी जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी रही। यही वजह थी कि एकलव्य ने अपने खेतों में कम लागत और कम पानी के साथ ही अधिक उपज प्राप्त होने वाली मसाला क्षेत्र विस्तार के तहत मिर्ची की फसल ली। ग्राम दुधवारा के युवा किसान एकलव्य साहू बताते हैं कि वे वर्ष 2017-18 में इंजीनियरिंग पास कर खेती-किसानी करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने उद्यानिकी विभाग से सम्पर्क किया। एकलव्य बताते हैं कि उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन से उन्हें राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई, पैक हाउस, बीज पैक योजना इत्यादि की जानकारी मिल और इसके लिए मिलने वाले अनुदान के बारे में भी पता चला। अनुदान का लाभ लेकर एकलव्य अपने 12 एकड़ क्षेत्र में मिर्च की फसल लेना शुरू कर दिए। वे बताते हैं कि उन्हें मिर्ची की खेती से प्रति एकड़ 100 से 110 क्विंटल उपज प्राप्त होती है और प्रति एकड़ दो लाख रूपये की शुद्ध आमदनी हासिल कर रहे हैं। एकलव्य कहते हैं कि वैसे तो उनके द्वारा तैयार मिर्ची जिले में ही हाथों-हाथ बिक जाती हैं, किन्तु वे अन्य जिलों में भी मिर्ची को बिक्री के लिए भेजते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भनवारटंक मालगाड़ी दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त करेंगे

बिलासपुर। बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर-अनूपपुर खंड के भनवारटंक में 26 नवम्बर सुपर लांग हाल मालगाड़ी सं एन/पीसीएमसी और एन/टीएसडब्ल्यूएस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच दक्षिण पूर्व सर्किल, कोलकाता के रेल संरक्षा आयुक्त श्री बी के मिश्रा करेंगें। जांच अधिकारी नियुक्त किये गये रेल संरक्षा आयुक्त श्री बी के मिश्रा 29 नवंबर को रेल प्रबंधक बिलासपुर कार्यालय में आयोजित वैधानिक जांच करेंगें जो पूरी होने तक जारी रहेगी इस दुर्घटना एवं इससे संबंधित मामले के बारे में जानकारी रखने वाले तथा साक्ष्य प्रदान करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति जांच की तारीख को उपरोक्त स्थान पर साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं अथवा रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व सर्किल, 14 स्ट्रांड रोड़, 12 वां तल, कोलकाता, 700001 को निम्न पते पर व ईमेल-crssec@gmail.com पर सूचित कर सकते हैं।

फैंसी दुकान में लगी आग दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची

जगदलपुर। शहर से करीब आठ किमी दूर आड़ावाल में गुरुवार की सुबह अचानक से एक फैंसी दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं, घटना के तत्काल बाद दमकल की गाड़ी के साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। जानकारी के अनुसार, आड़ावाल स्थित जय गुरु फैंसी स्टोर्स के ऊपर रखे सामान में अचानक से आग लग गई। आग लगने की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों ने एसडीआरएफ टीम के साथ ही दमकल की गाड़ी को सूचना दी, जहां तीन गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया। आग फैलने के चलते आसपास तीन और बड़ी दुकानें भी चपेट में आ सकती थी। समय रहते पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ टीम व दमकल की गाड़ी पहुंची। एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत देखी गई, लेकिन समय रहते आग को बुझाने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया।

टीआई सहित 38 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला

दुर्ग। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए टीआई, एसआई, एएसआई और हेड कॉन्स्टेबल सहित 38 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है। जिसमें 7 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक और 8 प्रधान आरक्षक समेत कुल 38 पुलिस कर्मी शामिल है। यह तबादला विभाग की कार्यकुशलता और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा अब अमलेश्वर थाना की प्रभारी होंगी। उनकी जगह दुर्ग थाने में पदस्थ एसआई अमित कुमार अंदानी को थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही स्मृति नगर चौकी प्रभारी वंदिता पानिकर को हटाकर डीएसबी का प्रभारी बनाया गया है। वंदिता के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रहीं थी क्योंकि उनकी चौकी में उनका हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते एसबीसी के द्वारा गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 7 अन्य थाना प्रभारियों को हटाया गया है उनमें अमलेश्वर थाना प्रभारी केशव राम कोसले को थाना प्रभारी पद्मनाभपुर बनाया गया है।

पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत

बिलासपुर। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को एसीबी-ईओडब्लू द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की एफआईआर मामले में उच्च न्यायालय से निराशा हाथ लगी है। उच्च न्यायालय की जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने एफआईआर पर स्टे देने से इनकार करते हुए एसीबी को एक हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगी। पूर्व महाधिवक्ता ने रायपुर की एसीबी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। रायपुर की एसीबी कोर्ट की जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सतीश चंद्र वर्मा ने गंभीर मामला बताते हुए हाई कोर्ट में अपील की है।

रायगढ़ में दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर

रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में पत्नी को लेने जा रहे बाइक सवार युवक एक अन्य बाइक से टकरा गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। वहीं, इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हो गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कंचनपुर निवासी सुरेंद्र कुमार सारथी (30) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह गाड़ी चलाने का काम करता है। उसी के गांव का रहने वाला घसियाराम राठिया कल शाम बाइक क्रमांक सीजी 13 एयू 7010 से अपनी पत्नी को लेने गुमडा जा रहा था। इसी दौरान वह उससे लिफ्ट लेकर पीछे बैठकर गुमडा जा रहा था। बाइक सवार दोनों युवक जब कंचनपुर मेन रोड पर पेड़ के आगे पहुंचे ही थे, तभी सामने की तरफ से आ रहे बाइक चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में घसियाराम राठिया के जबड़े के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में जोरदार चोट आई।

तस्करों पर एक्शन, पुलिस ने गांजा तस्कर को दबोचा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जीपीएम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिसमें पुलिस ने गांजे के एक प्रकरण में बैकवर्ड लिंक ट्रेस कर गांजा सप्लायर को ओडिशा के नक्सल प्रभावित जिले में दबिश देकर आरोपी गांजा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही में जुट गई है।

दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा रायपुर में एसपी, कलेक्टर्स की कांफ्रेंस ली गई थी। जिसमें कड़े शब्दों में मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्यवाही करने और तस्करों के फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक ट्रेस करने पर कहा गया था।

बीते सितंबर माह में थाना गौरेला के पीपरखूंटी खोंगसरा रोड पर पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर घेराबंदी की। दो अलग-अलग वाहनों से 105 किलो ग्राम गांजा जब्त किया था। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों बनवारी लाल गुप्ता उर्फ

पिंटू, रोहित गुप्ता और अंकुर जैतवार को मौके से गिरफ्तार किया।

वहीं एक अन्य फरार आरोपी गोपाल पनिका को साइबर सेल द्वारा मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए जीपीएम पुलिस को गांजा परिवहन के बैकवर्ड लिंक सप्लायर ओड़िशा बौध जिला निवासी अजीत राणा का पता चला जो सक्रिय रूप से सोनपुर ओडिशा के इलाके में गांजा बेच रहा था।

जिसके बाद जीपीएम पुलिस की टीम ओडिशा के जिला बौध निवासी अजीत राणा को साइबर सेल और थाना गौरेला की संयुक्त टीम ने उसके गांव में दबिश देकर सिलेतपाड़ा जिला बौध ओडिशा से गिरफ्तार किया है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल के कहा है। गांजा तस्करों के बैकवर्ड लिंक को ट्रेस कर पुलिस ने नक्सल प्रभावित गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और आरोपियों के संपत्तियों का चिन्हांकन भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के द्वारा उक्त गिरफ्तारी के लिए ओडिशा गई टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है।

आत्मनिर्भर बनाने का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों की ठगी

■ 10 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ितों ने पैसा वापस दिलाने सीएम से लगाई गुहार

कोरबा। जिले में विवादित कंपनी फ्लोरा मैक्स के करोड़ों के घोटाले मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पुलिस ने 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर इस स्कैम में टॉप टेन में थीं। यह स्पष्ट है कि यह मामला एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं ने गुरुवार को सीएम हाउस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कंपनी से अपना पैसा वापस दिलाने की मांग की।

इस मामले में पहले ही फ्लोरा मैक्स के डायरेक्टर अखलेश सिंह और केयर टेकर मया राम साहू को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि कंपनी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रलोभन देकर उन्हें ठगा। महिलाओं ने एसपी और कलेक्टर के पास अपने साथ हुई ठगी की

शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार की गई महिलाओं के पास से कंपनी द्वारा खरीदे गए आधा दर्जन से अधिक चारपहिया गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। एडिशनल एसपी यूवीएस चौहान ने का कहना है कि अभी मुश्किल है कि कुल कितनी महिलाओं के साथ इस कंपनी ने धोखाधड़ी की थी। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है। पुलिस आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी।

फ्लोरा मैक्स द्वारा किए गए इस घोटाले ने उन महिलाओं के विश्वास को तोड़ दिया, जिन्होंने कंपनी में निवेश करने का निर्णय लिया था। कंपनी ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था, लेकिन अंततः उन्होंने सामूहिक रूप से ठगी का शिकार बना दिए। अब पुलिस ने कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया है। आगे की कार्यवाही में अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।

क्षेत्र में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। कई लोग अपनी कमाई को लेकर चिंतित हैं। यह मामला न केवल महिलाओं के आत्मनिर्भरता के सपने को झकझोर दिया है, बल्कि समाज में ऐसी धोखाधड़ी को उजागर करने का काम भी करता है, जो स्थानीय स्तर पर हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में सतर्क रहें और अपनी शिकायतें समय पर दर्ज कराएं। वहीं इस मामले को लेकर कोरबा क्षेत्र की महिलाओं ने आज रायपुर पहुंचकर सीएम हाउस में ज्ञापन सौंपा और कंपनी से अपना पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई।

कांग्रेस नेताओं में तू तू -मै मै,पूर्व महापौर को नोटिस

बिलासपुर। बुधवार को न्यायधानी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में जिला प्रभारी प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल और कांग्रेस नेता व पूर्वमहापौर राजेश पांडे के बीच विवाद हो गया था। पूरा विवाद बड़े नेताओं के बैठक के दौरान सामने आया था। हालांकि दूसरे नेताओं ने दखल देते हुए मांमले को शांत करा दिया। खुद बैज की मौजूदगी में हुए इस विवाद ने कांग्रेस के भीतर के अंतरकलह को सामने ला दिया था। वही अब मामले में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजेश पांडे को नोटिस थमाते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल बुधवार को बिलासपुर के कांग्रेस भवन में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संबंध में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए थे। बैठक पूर्व महापौर राजेश पांडे को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद राजेश पांडे और सुबोध हरितवाल के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। इस कुछ अशोभीनीय बातें भी कह दी गई। हालांकि बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की। बाद इसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी।

एनएसयूआई ने की विलंब शुल्क माफ करने की मांग, कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। जिला एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने में हो रही तकनीकी समस्याओं के कारण विलंब शुल्क माफ करने की मांग की गई। एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल में बार-बार आ रही तकनीकी खामियों की वजह से कई छात्र समय पर फॉर्म नहीं भर सके। इसके चलते छात्रों को अनावश्यक रूप से विलंब शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए विलंब शुल्क को तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए। एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष तारिक अनवर खान ने कहा, यह छात्रों की गलती नहीं है कि पोर्टल सही ढंग से काम नहीं कर रहा। विश्वविद्यालय को इस समस्या की जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों को राहत प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और सुगम बनाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश सचिव अतिक मेमन, जिला महासचिव संस्कार पांडेय, वरुण चावड़ा, आशीष बाजपाई उपस्थित रहे।

मंत्री कश्यप आज बेमेतरा में करेंगे सहकारी बैंक का शुभारंभ

रायपुर। सहाकारिता मंत्री केदार कश्यप 29 नवंबर को बेमेतरा जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की 4 नवीन शाखा का शुभारंभ करेंगे। ये शाखाएं नवागढ़ तहसील के ग्राम बदनारा, कन्हेरा, सत्धा और गोड़गिरी में प्रारंभ होंगी। सहकारिता मंत्री इन शाखाओं का शुभारंभ ग्राम बदनारा से करेंगे। शुभारंभ समारोह दोपहर 3 बजे से होगा। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दुर्ग लोकसभा की सांसद विजय बघेल अति विशिष्ट अतिथि, विधायक दिपेश साहू एवं ईश्वर साहू विशिष्ट अतिथि तथा जिला पंचायत बेमेतरा की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता साहू वरिष्ट समाज सेवी ओम प्रकाश जोशी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

15 किलो गांजा के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

रायपुर (असं)। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत रिंग रोड नंबर 01 के केनाल रोड फ्लाई ओवर के नीचे गांजा तस्करी करते हुए दो अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 15 किलो 860 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत रु. 1,50,000 है। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। नारकोटिक्स एक्ट के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया। 27 नवंबर को सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति अपने बैग में गांजा लेकर रिंग रोड नंबर 01 के केनाल रोड फ्लाई ओवर के नीचे खड़े हैं।

रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना 140 किमी का 3,513.11 करोड़ रुपये का डीपीआर बन गया है - कश्यप

जगदलपुर। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन रेल मंत्री से सीपेस की जानकारी मांगी। सत्र के दूसरे दिन 27 नवंबर को बस्तर सांसद ने एक बार फिर छत्तीसगढ़-बस्तर के रेल विषयों पर रेल मंत्री से प्रश्न कर जानकारी मांगी है। सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय रेल मंत्री से निम्नलिखित तीन विषयों पर जानकारी प्रदान करने को लेकर प्रश्न किया, जिसमें 2014 से आज तक देश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में वर्षवार कितनी रेल पटरियां बिछाई गईं और रेलगाडियां शुरू की गईं। 2014 से आज तक देश भर में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लिए कितनी नई रेल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। कुल परियोजनाओं में से स्वीकृत परियोजनाओ की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना बजट आवंटित किया गया है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बताया कि केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना का दूसरे चरण के लिए 140 किमी डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसकी लागत 3,513.11 करोड़ रुपये है।

इन विषयों पर केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रेषित किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान देशभर में लगभग 2.32 लाख करोड़ रुपये की लागत की 19,748 किमी लंबाई वाली 309 परियोजनाएं नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण, स्वीकृत की गई हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अंशतः पडने़ वाली 10,182 करोड़ रुपये की लागत की 1,225 किमी कूल लंबाई वाली परियोजनाएं (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण शामिल हैं। बस्तर जिले से गुजरने वाली दल्लीराजहरा, रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना 235 किमी को दो चरणों दल्लीराजहरा रावघाट 95 किमी और रावघाट-जगदलपुर 140 किमी में शुरू किया गया है। चरण-। अर्थात् दल्लीराझरा रावघाट में 77 कि.मी. दल्लीराझरा-ताड़ोकी को कमीशन कर दिया गया है। इस परियोजना पर 31 अप्रैल 2024 तक 1,028 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। चरण-॥ अर्थात रावघाट-जगदलपुर 140 किमी की विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है, जिसकी लागत 3,513.11 करोड़ रुपये है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में पूर्णतःअंशतः रूप से पडने़ वाली निम्नलिखित नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं।धमतरी बांसकोट, कोडागांव 183 किमी, गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली 490 किमी और कोठागुड़ेम-किरंदुल 180 किमी, चूंकि रेल नेटवर्क राज्य और जिले की सीमाओं के आर-पार फैला होता है, इसलिए गाडियों को ऐसी सीमाओं के आर-पार नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार चलाया जाता है। वर्ष 2014-2015 से 2023-24 की अवधि के दौरान देश में 1931 गाड़ी सेवाएं आरंभ की गई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित स्टेशनों को सेवित करने वाली निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं।

507 न्योता भोज आयोजित, 29251 विद्यार्थी हुए शामिल

महासमुंद। नेवता भोज कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से समरसता की ओर एक बेहतर और अनूठा पहल है। इससे समाज और शिक्षा का तालमेल बेहतर होते दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप 16 फरवरी से शुरू हुई इस योजना से पालक से दानदाताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों द्वारा स्कूलों में जाकर अपने बच्चों के साथ स्कूल में पढने़ वाले सभी बच्चों के संग खुशियां बांट रहे हैं।

महासमुंद जिले में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक नई पहल ने न केवल उनके पोषण स्तर को सुधारा है, बल्कि शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के महत्व को भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत चलाए जा रहे न्योता भोजन कार्यक्रम ने बच्चों और समुदाय के बीच एक गहरी सकारात्मक छाप छोड़ी है। न्योता भोज कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को गति मिले। इस कार्यक्रम में दानदाताओं, सामाजिक संगठनों, और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर स्कूलों में विशेष भोजनों का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को न केवल पोषक आहार मिला, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर भी जागरूक किया गया।

महासमुंद जिले में 507 बार आयोजित इस कार्यक्रम से कुल 29,251 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। बागबाहरा विकासखंड में 238 आयोजनों में 13,484 बच्चों को पोषक आहार प्रदान किया। सरायपाली में 70 आयोजनों के माध्यम से 4,406 छात्रों ने लाभ उठाया। इसी तरह, पिथौरा, बसना, और महासमुंद विकासखंडों में क्रमशः 45, 60, और 94 आयोजन सफलतापूर्वक किए गए।

समिति के माध्यम से विगत वर्ष 39 क्विंटल बीज हुआ था वितरित, वही 30 गुणा की वृद्धि के साथ इस वर्ष 1211.64 क्विंटल बीज का किया गया वितरण

धमतरी। प्राकृतिक संसाधनो से आच्छादित छत्तीसगढ़ और सुनहरे धान की बालियों से सौन्दर्य बोध कराता जिला धमतरी में खरीफ में बहुतायत में धान उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे धनहा धमतरी भी कहते है। वैसे तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है तथा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने में धमतरी जिले का महत्वपूर्ण योगदान है, किन्तु कृषक अब ग्रीष्मकालीन धान का मोह त्याग कर दलहनी/तिलहनी फसल लगाने हेतु सामने आ रहे है।

कृषको के उत्साह को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। विगत दिनो जल संरक्षण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जिले में जल जगार कार्यक्रम का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। साथ ही कृषि एवं संबंधित विभागो द्वारा 182 ग्रामो में दलहन, तिलहन फसलो को प्रोत्साहित करने हेतु जनजागरूकता शिविर लगाया गया।

इसी प्रकार 48 ग्रामो में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां दलहन, तिलहन फसलो के उत्पादन के फायदे बताये जा रहे है, वही उन्त बीज व किस्म के साथ-साथ कृषि कार्य तथा रबी ऋण पर व्यापक जानकारी दी गई। नतीजन जिले के किसान बढ़-चढ़कर दलहन, तिलहन और नगदी फसलो की बुआई करने लगे है।

गौरतलब है कि रबी वर्ष 2023-24 में दलहन, तिलहन फसल मात्र 15 हजार हेक्टेयर रकबे में आच्छादित था, वही इस वर्ष यानी रबी वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष का आंकड़ा पार करते हुए 19 हजार चार सौ सैतालीस हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो चुकी है तथा अभी भी बुआई कार्य प्रगतिरत है। अन्न वाली फसल-गेंहू, मक्का, रागी 451 हेक्टेयर, दलहन फसल- चना, मटर, मसूर, उड़द, तिवडा 13 हजार 170 एवं तिलहन फसलो का क्षेत्राच्छादन 4 हजार 107 हेक्टेयर क्षेत्र में है। इस तरह कुल 19 हजार 447 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलो का क्षेत्राच्छादन पूर्ण हो चुका है, रबी फसलो की पछेती बुआई मध्य दिसंबर से अंतिम दिसंबर तक सम्पन्न होती है तथा ग्रीष्मकालीन उडद, मूंग एवं तिल की बुआई माह फरवरी में होगी। जिला प्रशासन द्वारा इस रबी वर्ष में 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन, तिलहन फसलो के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि रबी वर्ष बुआई की समाप्ति तक लक्ष्य से ज्यादा रकबे में आच्छादित होने की सम्भावना है।

जिले में विगत वर्ष समिति के माध्यम से मात्र 39 क्विंटल बीज का वितरण किया गया था, किन्तु इस वर्ष संयुक्त प्रयास से समिति के माध्यम से 1211 क्विंटल 64 किलोग्राम बीज का वितरण किया जा चुका है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 30 गुणा अधिक हैं। इसी तरह योजनाओं से गत वर्ष 1550 हेक्टेयर रकबे में फसल उत्पादन किया गया था, वही इस वर्ष दलहन, तिलहन फसलो का 7 हजार 552 हेक्टेयर रकबे हेतु बीज का वितरण किया गया है। कृषक अब जल संवर्धन की महत्ता को समझने लगे है एवं क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से सम्पर्क कर दलहन, तिलहन और नगदी फसलो के उत्पादन की तकनीकी जानकारी ले रहे है।

रोहताड़ के ग्रामीणों को मिल रहा शुद्ध पानी, जीवन में आई खुशहाली

नारायणपुर। जिले के छोटे से गांव रोहताड़ कई सालों से पानी की भारी समस्या से जूझ रहा था। यहां पानी की कमी और दूषित जल ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर गंभीर असर डाला था। महिलाओं को रोज़ घंटों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था और अक्सर पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण परिवार में बीमारियां भी बढ़ती रहती थीं, जिससे ग्रामीण परेशान थे और उन्हें इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दिख रहा था। 2019 में सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने रोहताड़ के ग्रामीणों को एक नई उम्मीद दी। जल जीवन मिशन के तहत् हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और रोहताड़ भी इस योजना का हिस्सा बना। स्थानीय अधिकारियों और जल जीवन मिशन की टीम ने गांव के जलस्रोतों का निरीक्षण किया और एक विस्तृत योजना बनाई। इस योजना के तहत् 10 हजार लीटर क्षमता वाली 3 सोलर टंकियों का निर्माण किया गया जो सौर ऊर्जा से चलती हैं। इन टंकियों में दूर-दूर से पानी लाकर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर इसे पूरे गांव में पाइपलाइनों के जरिए घर-घर तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए 2 हजार 900 मीटर पाइपलाइन बिछाया गया है.

बस्तर में वनभूमि पट्टा के लालच में अवैध कटाई के कारण साल वन का रकबा आधे से भी कम हुआ

जगदलपुर। साल वनों का द्वीप के नाम से पहचाने जाने वाले बस्तर में अब अवैध कटाई के कारण साल वन का रकबा लगातार घटता जा रहा है, वहीं पिछले कुछ सालों से वनभूमि पट्टा के लालच में ग्रामीण साल के बड़े-बड़े पेड़ों को काट डाले और यह कार्य वर्तमान में भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बस्तर में साल वन का रकबा वर्तमान में 895.76 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है, जबकि दो दशक पहले सालवन का रकबा 2 हजार वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित रहा। बीते 30 सालों में 400 से ज्यादा बस्तियां वनांचल में बस चुकी हैं. अभी भी हरे-भरे विशाल पेड़ो की गडलिंग कर इन्हें सुखाकर जलाने और बेचने का खेल धड़ल्ले से जारी है।

दरअसल बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीणों की जरूरत को देखते हुए वनांचल के भूमिहीन बाशिंदों को खेती किसानी के लिए वन भूमि अधिकार प्रपत्र दिया जा रहा है. इसके लिए बकायदा वन विभाग, जिला पंचायत ,राजस्व विभाग की टीम बनाई गई है और प्रत्येक भूमिहीन को चार हेक्टेयर यानी की 10 एकड़ वन भूमि देने का प्रावधान है। नियम के अनुसार जिन ग्रामीणों को यह वन भूमि अधिकार प्रपत्र दिया गया है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि ग्रामीण वन भूमि पर खेती करेंगे लेकिन वहां खड़े पेड़ों को नहीं काटेंगे, अगर वैसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के चलते अब तक जगदलपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत ही लगभग 32 हजार हेक्टेयर वन भूमि ग्रामीणों को दिया जा चुका है। मार्च 2019 तक जगदलपुर वन वृत में 28, 350 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा हो चुका था, समिति के अनुसंशा पर 16 हजार 754 लोगों को व्यक्तिगत और 694 सामूहिक वन अधिकार प्रपत्र दिया जा चुका है।

उल्लेखनिय है कि बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है, साल वनों के कारण ही दो दशक पहले तक बस्तर में अच्छी बारिश होती थी।

गर्मी के सीजन में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार नहीं करता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से तापमान मई-जून में 40 डिग्री को पार कर लेता है। पूर्व में साल के पेड़ों की तस्करी होती रही पर जब से वनभूमि पट्टा वितरण शुरू हुआ, तब से जंगल की अंधाधुंध कटाई हुई। अंदरूनी इलाके में भी ग्रामीण बड़े-बड़े साल के पेड़ों की कटाई किए, इसके कारण अब और अधिक रकबा में कमी आई है। वोट बैंक की राजनीति से उपर उठकर रजनैतिक दलों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले दिनों में इसके भयावह परिणम देखने के लिए बस्तर को तैयार रहना चाहिए।

बस्तर के मुख्य वन संरक्षक आरसी दुग्गा का कहना है कि पिछले सरकार के शासन के नियमों के तहत ही भूमिहीन लोगों को पट्टा वितरण किया गया। हालांकि लगातार विभाग में यह शिकायत मिल रही है कि वन अधिकार पट्टाधारी लगातार खड़े पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे बस्तर में जंगलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। खासकर वन भूमि क्षेत्र में पुराने पेड़ों की कटाई की जा रही है, हालांकि ऐसे लोगों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन कई बार वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सामूहिक वन अधिकार पट्टा देने पर उसमें दिक्कतें सामने नहीं आती है, लेकिन भूमिहीन बाशिंदों को वन अधिकार पट्टा वितरण के बाद उनके द्वारा सारे नियमों को ताक में रखकर वन अधिनियमो का उल्लंघन किया जाता है।

सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, मुआवजा मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

बसना। बुधवार की रात में राष्ट्रीय राजमार्ग पर छुईपाली टोल नाका के पास पिकअप वैन को ओवर टेक कर आगे निकलने के प्रयास बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृत युवकों के परिजन और ग्रामीणों ने उचित मुआवजे और पिकअप वाहन के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग को लेकर शवों को सड़क पर ले धरने पर बैठ गए जिससे घंटों तक यातायात बाधित रहा। बसना में सड़क हादसे मे तीन लोगों की मौत ने तूल पकड़ लिया है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने शव को एनएच 53 पर रखकर चक्का जाम किया। छुईपाली टोल प्लाजा में बड़ी संख्या मे परिजन और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक के परिवारों को उचित मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। बुधवार की रात हुए इस भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर छुईपाली टोल नाका के पास ओवर टेक कर रहे तीन बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने कुचल दिया। हादसे में मारे गये तीनों युवक बसना थाना अंतर्गत पास के गांव के रहने वाले थे।

चिटफंड कंपनियों से धोखा खाई महिलाएं पहुंची मुख्यमंत्री निवास, बैठी धरने पर

रायपुर। चिटफंड फ्लोरा मैक्स चिटफंड ने दोगुने से अधिक रुपये मिलने का लालच देकर कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले की सैकड़ों महिलाओं को अपने जाल में फंसा लिया और इससे पीड़ित महिलाएं गुरुवार को मुख्यमंत्री निवासी पहुंचकर धरने पर बैठ गई। वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाह रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्लोरा मैक्स चिटफंड ने दोगुने से अधिक लाभ का लालच देकर कोरबा और जांजगीर-चांपा की महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें निवेश करने के मजबूर कर दिया और ये महिलाएं उनकी जाल में आकर 30-40 हजार रूपए लोन लिया ले लिया। फ्लोरा मैक्स कंपनी से न दोगुना लाभ मिला न मूलधन इसके बाद महिलाओं ने कोरबा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई इसके बाद पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन लोन देने वाले निजी बैंकों के वसूली एजेंट और कर्मचारी उनके घरों में आकर महिलाओं को परेशान कर रहे है। इनसे त्रस्त सैकड़ो महिलाएं गुरुवार को राजधानी पहुंची और मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर जा बैठीं। सभी महिलाएं बैंक से लिया लोन माफ करवाने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात करना चाह रही थी लेकिन वे मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाई। इन महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। फिलहाल सिविल लाइंस पुलिस इन महिलाओं को समझाइश देने में जुटे हुए है।

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

संशोधन क्र.-1

निविदा सूचना क्रमांक:14/ व.ले.लि./2024-25, दिनांक 11/11/2024 निविदा सिस्टम क्र. 161007 एवं निविदा सूचना क्रमांक: 15/व.ले.लि./2024-25, दिनांक 11/11/2024 निविदा सिस्टम क्र. 161072 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

S. No.	Item	Previous issue	Amendment
1.	ITEM RATE TENDER, FORM - B (ENVELOPE - 'C')	Clause 2.8.1	Amended as per Government of C.G., W.R. Deptt. letter No 4515/F-7-7/S-2/31/2001 Date 25/11/2024 Attached.
2.		Clause 4.3.36	Amended as per Government of C.G., W.R. Deptt. letter No 4504/F-7-7/F-2/31/2001 Date 22/11/2024 Attached.

निविदा की अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।
1. विज्ञापन .क्र. 24251004663 दिनांक 15.11.2024
2. विज्ञापन.क्र. 242503771 दिनांक 16.11.2024

कार्यपालन अभियंता
खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

जी-242504115/7

महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता पक्ष को फिर मिला जनादेश

सुरेश हिंदुस्तानी

देश के दो राज्यों के साथ कुछ राज्यों के उपचुनाव के परिणाम ने सत्ता पक्ष के प्रति अपना जनादेश दिया है। हर चुनाव में सत्ता के प्रति जनता में किसी न किसी बात पर आक्रोश रहता है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जनता ने फिर से उन्हीं सरकारों को फिर से सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी है, जो सत्ता में थी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखण्ड में सत्ता धारी गठबंधन को पहले से ज्यादा सीटें मिली हैं। यह जनादेश न तो किसी के उछलने का मार्ग तैयार करता है और न ही किसी को नकारने की स्थिति पैदा करता है। जहां तक खुशियाँ मनाने की बात है तो महाराष्ट्र में भाजपा नीत गठबंधन जीत की खुशी मना रहा है तो झारखण्ड में इंडी गठबंधन के गले में विजयी माला पहनाई गई है। वहीं उपचुनाव में सबको खुशी और सबक दोनों ही दिए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अपने हिसाब से राजनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के लिए इन चुनावों में प्रादेशिक रूप से जय और पराजय दोनों ही सन्देश प्रवाहित हो रहे हैं। किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम की स्थिति पैदा करने वाले परिणाम ने यह तो साबित कर दिया है कि देश में किसी एक राजनीतिक दल का न तो व्यापक प्रभाव है और न ही कम सीट प्राप्त करने वाले को कमतर आँका जा सकता है। इस चुनाव की सबसे ख़ास बात यह मानी जा सकती है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सकी, जिससे यह सन्देश निकल रहा है कि अब भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा गठबंधन के सहारे ही तय होगी। वर्तमान में राजनीति दो विचार धाराओं के बीच है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बनाकर चलने वाले राजनीतिक दलों का विचार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विचारों से तालमेल रखने वाले दलों की बानगी है। इतना ही नहीं इन चुनावों एक दूसरे के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वह राजनीतिक हिसाब से भले ही जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन आम नागरिकों के समक्ष भ्रम जैसी स्थिति को ही प्रादुर्भित करती हैं। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए निश्चित ही अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन झारखण्ड में सरकार बनाने का सपना लेकर मैदान में उतरी भाजपा को फिर से तैयारी करनी होगी। झारखण्ड के परिणाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति उपजी सहानुभूति को आधार बताया जा रहा है। पिछले दिनों झारखण्ड में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से अलग होना पड़ा था। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने चुनाव में इसी को अपना राजनीतिक हथियार बनाया था और चुनाव में अपने पक्ष में वातावरण बनाया। ऐसा लगता है कि झारखंड में भाजपा अपनी ताकत और कमजोरी को भाँपने में विफल हो गई। झारखण्ड में भाजपा इतनी अप्रभावी नहीं कही जा सकती, जैसा उसका इस चुनाव में प्रदर्शन रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा के प्रादेशिक नेताओं की तनातनी जगजाहिर थी, जिसका परिणाम भाजपा के लिए ठीक नहीं था। हालाँकि इस चुनाव में भाजपा ने पिछली गलती को सुधारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह सत्ता के सीढ़ी का निर्माण कर पाने में असफल रही। अब झारखण्ड में फिर से झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री होंगे, यह भी तय लगता है। परिणाम के बाद अब महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में जो राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में राजनीतिक हवा अलग अलग दिशा में बह रही थी। जिसने हवा का रुख भांप लिया, वह हवा के साथ ही चला और सत्ता प्राप्त करने में सफलता हासिल की। महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के साथ रहने वाले शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार कर शायद यही सन्देश दिया है कि यह सत्ता के लिए किया गया बेमेल गठबंधन ही था।

महाराष्ट्र में भाजपा की जीत का राष्ट्रीय राजनीति में दिखेगा असर

आरती आर जेरथ

झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत भले मिली हो, लेकिन नतीजे स्पष्ट करते हैं कि इस जीत का पूरा श्रेय हेमंत सोरेन और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद उठी सहानुभूति की लहर और आदिवासी वोटों के एकीकरण के दम पर अपने लिए दूसरा कार्यकाल जीत लिया।

पहली नजर में देखें, तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों का स्कोर कार्ड बराबरी पर रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाले महायुति ने महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ किया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन झारखंड में अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल रहा। हालांकि महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा संचालित महायुति की जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि इसका असर निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें 48 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिहाज से देश का सबसे अमीर राज्य है। सबसे खास बात यह है कि यह देश की वित्तीय राजधानी यानी मुंबई का घर भी है। जाहिर तौर पर जो पार्टी महाराष्ट्र पर राज करती है, उसका राजनीतिक कद बहुत बढ़ जाता है।

हरियाणा में कांग्रेस की चुनौती को धूल चटाने के एक महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में ?भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं उसने महायुति के अपने सहयोगियों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत गिरावट के उस आख्यान को भी पलट दिया, जो लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े को छूने में हुई विफलता के साथ शुरू हुआ था। यह जीत इस बात का स्पष्ट संदेश देती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक हार से अपना और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाली पार्टी नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक चुनावी हार के बाद भाजपा खेल में वापस आने के लिए और विरोधियों को पस्त करने लिए अपनी जीत की जमीन व रणनीति तैयार करने में जुट जाती है और इस बार भी उसने ठीक यही किया। अपने सहयोगियों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ महायुति ने राज्य के सभी छह क्षेत्रों में निर्णायक रूप से जीत हासिल की और राज्य विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में चार दशक से भी अधिक समय पहले कांग्रेस के उत्कर्ष काल के बाद से किसी भी सत्तारूढ़ गठबंधन ने इस आंकड़े को नहीं छुआ है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से मिली करारी हार (महाराष्ट्र की 48 में से महायुति को 17 सीटें ही मिली थीं) से आहत महायुति ने अपने गठबंधन में सुधार करने के साथ ही अपनी छवि को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। तमाम प्रयासों का ही नतीजा है कि विधानसभा चुनाव में महायुति को एकतरफा जनादेश मिला है।

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी महायुति को मिली प्रचंड जीत का श्रेय कई कारकों को जाता है। लोकप्रिय लाडकी बहिन योजना के जरिये महिलाओं के खाते में सीधी धनराशि भेजी गई, विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों के असंतोष को शांत करने के लिए कई कल्याणकारी लाभ दिए गए, मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे पाटिल को अपना आंदोलन वापस लेने के लिए मनाया गया और मोदी के करिश्माई नारे 'एक हैं तो सेफ हैं' ने हिंदू मतदाताओं को महायुति के पक्ष में एकजुट करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकसभा चुनाव के दौरान नदारद रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवकों ने शांतिपूर्ण ढंग से जमीनी स्तर पर अभियान चलाया।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी हैं। इनमें एक है स्थानीय नेताओं का बढ़ता महत्व। हरियाणा और महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में भाजपा ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर ही निर्भर न रहते हुए, अपने राज्य के नेतृत्व को भी आगे रखा। दूसरी बात यह कि इस जीत से इस बात की भी पुष्टि होती है कि कांग्रेस सीधे तौर पर अब भाजपा का मुकाबला करने में असमर्थ है। देश की सबसे सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने अब तक के सबसे कम स्कोर के साथ सीटों की संख्या के मामले में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने जिन सौ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, उनमें करीब सत्तर सीटों पर भाजपा के साथ आमने-सामने की लड़ाई थी। इनमें से कांग्रेस बीस सीटें भी नहीं जीत पाई। तीसरा निष्कर्ष यह है कि ये नतीजे शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे सेना के साथ-साथ अजीत पवार की राकांपा और चाचा शरद पवार के गुट के बीच विरासत की लड़ाई का भी समाधान करते हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, दोनों ही अपनी पार्टियों के नेतृत्व का दावा करने के लिए विजेता बनकर उभरे हैं।

चौथा और यह शायद सबसे अधिक चौंकाने वाला निष्कर्ष, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बुजुर्ग नेता शरद पवार की चमक का फीका पड़ना है। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से चार दशकों तक राज्य की राजनीति पर प्रभुत्व जमाकर रखा, जिसके दम पर उन्होंने कई सरकारें बनाई और गिराई भी हैं। लेकिन इस बार वह पूरी तरह विफल हो गए और अपने गढ़ पश्चिमी महाराष्ट्र को भी नहीं बचा सके। इस क्षेत्र में उनके भतीजे अजीत पवार के गुट ने राकांपा बनाम राकांपा की लड़ाई में ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। शरद पवार ने खुद घोषणा की थी कि यह उनका अंतिम चुनाव है। इस दिग्गज के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 84 साल की उम्र में और कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद वह अपने लिए राजनीति से एक सम्मानजनक विदाई की पटकथा लिखने में विफल रहे।

हालांकि झारखंड में मिली जीत इंडिया गठबंधन के लिए एक आशा की किरण है। कांग्रेस इसका सही उपयोग भाजपा को जवाब देने के लिए कर सकती है, लेकिन नतीजे स्पष्ट करते हैं कि इस जीत का पूरा श्रेय हेमंत सोरेन और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति की लहर और आदिवासी वोटों के एकीकरण के दम पर अपने लिए दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए कांग्रेस का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। सोरेन के अभियान का मुख्य मुद्दा-आदिवासी पहचान का संरक्षण और आदिवासियों के सरना कोड के लिए सांविधानिक दर्जा रहा, जो भाजपा के बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भारी पड़ता दिखा। चूंकि सांविधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, महाराष्ट्र में अगली सरकार 26 नवंबर तक बननी है, इसलिए महायुति इस जटिल प्रश्न को निपटाने के लिए तेजी से कदम उठाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एकनाथ शिंदे या ?भाजपा के देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई और? खैर, इस बहस के जवाब पर अटकलें लगाने का अब कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हुए 25 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में, महाराष्ट्र में मिली जीत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों में अपनी पांच सीटों को बरकरार रखने के अलावा समाजवादी पार्टी से दो सीटें छीनने में भी कामयाब रही भाजपा के अधिक आक्रामक दिखने की उम्मीद है।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने वाली बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में अपने शस्त्रागार में एक अतिरिक्त तीर से जरूर युक्त हुए हैं। उम्मीद है कि वह उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ जारी अमेरिकी गिरफ्तारी वारंट को लेकर मोदी सरकार पर अपने सभी शस्त्र चलाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी का हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, वह उनकी धार को कुंद ही करेगा। फिलहाल यह भी तय नहीं है कि प्रमुख व्यवसायी पर हमला करने के लिए राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के ही उनके साझेदारों से कितना समर्थन मिलेगा, क्योंकि अदाणी का न केवल कई राज्यों में भारी निवेश है, बल्कि मोदी सरकार के साथ भी उनके करीबी संबंध हैं। महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जिसकी उसे लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद से तलाश थी।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

हुज्जतों को मरम्मत कभी दयानन्दी समाज की ओर से पुराणों के प्रामाण्य उड़ाने के लिए शास्त्रोक्त प्रमाण तथा युक्तियों को छोड़ कर हुज्जतबाजी का भी आश्रय लिया जाया करता है, और डूबते को तिनके का सहारा वाली लोकोक्ति के अनुसार इसी टांय टाँय के बल पर वे कुछ और देर तक किसी तरह सितकते रहना चाहा करते हैं।

वे प्राय: कह दिया करते हैं कि- क्या वेदादि शास्त्रों में पुराण शब्द आ जाने से वर्तमान अठारह पुराण सिद्ध हो सकते हैं? यहां तो पुराण शब्द का अर्थ पुरा ण-विद्या है। यदि सामर्थ्य है तो वेदों में ब्रह्म-पद्म विष्णु आदि नाम दिखा दो, जिससे हम अनुमान कर सकें कि वास्तव में, वेदादि ग्रंथों में वर्तमान पुराणों का उल्लेख है, इत्यादि.. - यह है वह हुज्जत, जिसके बल पर पुराणों को उड़ाने की अन्तिम कुचेष्टा की जाया करती है! यदि इन बुद्धि के हिमालयों से कोई पूछे कि वह पुराणविद्या किस ग्रन्थ में णित है ? कुरान में या बाईबिल में ? बस ! जिस ग्रन्थ में यह पुराणविद्या वर्णित है उसे ही हम आदिम-पुराण के नाम से पुकारते हैं और उसी में संक्षिप्त रूप से वर्तमान अठारह पुराणों का संकलन मानते हैं। रहा अष्टादश पुराणों के नाम वेद में दिखाने का प्रश्न? सो सूत्रग्रन्थों तक में तो निर्विवाद भविष्यत् पुराणादि का स्पष्ट नाम लिखा मिलता है। यह बात मि0 एफ0 ई0 पाजिटर आदि पाश्चात्य पण्डितों ने भी एक स्वर से स्वीकार की है। नि:सन्देह सूत्रकाल वैदिककाल का अत्यन्त निकटवर्ती है। इतने पर भी यदि वेदों में ही पुराणों के नाम देखने का चाव है तो हम दयानन्द जी की वेदोक्त तार विद्या की तरह वैदों में भी अठारहों पुराणों के नाम दिखा सकद्यै हैं और पण्डित मण्डल में आज जितना दयानन्द प्रदर्शित रैल तार बिजली आदि की वैदिकता का मूल्य है खसप्से भी अधिक हमारे चुने अष्टादश पुराणों के नामों का हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस

विकास

अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को जगुआर के सामने बढ़ते खतरों और मेक्सिको से अर्जेंटीना तक इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को जैव विविधता संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण प्रजाति, सतत् विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है।

जगुआर लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ा मांसाहारी और एकमात्र बड़ी बिल्ली है, जो मेक्सिको से अर्जेंटीना तक 18 देशों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ओंका है। जगुआर ने अपने प्राकृतिक आवास रेंज में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान का अनुभव किया है। जगुआर को अक्सर तेंदुए के रूप में समझा जाता है, लेकिन उनके शरीर पर हो रहे धब्बे से उन्हें विभेदित किया जा सकता है। इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में जगुआर कॉरिडोर और उनके आवासों के संरक्षण की जरूरत पर ध्यान आकर्षित करना है।

मार्च 2018 में जगुआर 2030 फोरम के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 रेंज देशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए। इस फोरम के परिणामस्वरूप जगुआर 2030 स्टेटमेंट अस्तित्व में आया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी जगुआर संरक्षण पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित किया। इस पहल का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों को जोड़कर और उनके प्राकृतिक क्षेत्र में उनके लिए सुरक्षित गलियारे बनाकर जगुआर के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना था। रोडमैप मानव-जगुआर संघर्ष और अवैध शिकार को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह दिन उन पारिस्थिति की प्रणालियों को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है जहाँ जगुआर रहते हैं, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन और घास के मैदान। यह स्वदेशी समुदायों के लिए जगुआर के सांस्कृतिक महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने वाली स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देता है। विभिन्न संगठन, वन्यजीव फाउंडेशन और संरक्षण समूह इस दिन जगुआर के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

ब्राजील सहित कई रेंज देश राष्ट्रीय जगुआर दिवस समारोह भी मना रहे हैं, जिसने जगुआर को जैव विविधता के प्रतीक के रूप में मान्यता दी है। जगुआर दिवस मनाने की मांग करने वाले वैश्विक जंगली बिल्ली संरक्षण संगठन, पैंथेरा के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ और मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एलन रैबिनोविट्ज़ शामिल थे।

कनाडा एवं अमेरिका से भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन की सम्भावना बढ़ रही

प्रह्लाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर लगातार कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई दे रही हैं, जिससे विशेष रूप से कनाडा एवं अमेरिका से भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन की सम्भावना बढ़ती जा रही है। कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी आंदोलन के चलते वहां निवासरत भारतीयों एवं मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं एवं भारतीयों एवं मंदिरों पर हो रहे इन हमलों पर लगाम लगाने में कनाडा की वर्तमान सरकार असफल सिद्ध हो रही है एवं इन हमलों को, राजनैतिक कारणों के चलते, रोकने की इच्छा शक्ति का अभाव भी दिखाई दे रहा है। इसके चलते भारत एवं कनाडा के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रिश्तों पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि भारत ने कनाडा में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम कर दिया है तथा भारत ने कनाडा को निर्देशित किया था कि वह भी भारत में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम करे। भारत एवं कनाडा के बीच आज कूटनीतिक रिश्ते आज तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। साथ ही, कनाडा में आज सुरक्षा की दृष्टि से भी स्थितियां तेजी से बदल रही हैं तथा इसका कनाडा के आर्थिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके चलते भारतीय आज कनाडा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और भारत की ओर रूख कर रहे हैं।

दूसरी ओर, अमेरिका में डोनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के पश्चात वहां पर अवैध रूप से रह रहे अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकाले जाने की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या लगभग नगण्य सी ही है परंतु ट्रम्प प्रशासन द्वारा अब वीजा, एच1बी सहित, जारी करने वाले नियमों को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले कुल एच1बी वीजा में से 60 प्रतिशत से अधिक वीजा भारतीय मूल के नागरिकों को जारी किए जाते हैं। यदि इस संख्या में भारी कमी दृष्टिगोचर होती है तो अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को, उनकी पढ़ाई सम्पन्न करने के पश्चात यदि एच1बी वीजा जारी नहीं होता है तो उन्हें भारत वापिस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिका से भी भारतीयों का रिवर्स ब्रेन ड्रेन दिखाई पड़ सकता है।

भारत आज पूरे विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, अत: भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास के कारण सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, उच्च तकनीकी क्षेत्रों, वाहन विनिर्माण उद्योग, फार्मा उद्योग, चिप विनिर्माण उद्योग, स्टार्ट अप, आदि क्षेत्रों में भारी मात्रा में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं और भारत को इन क्षेत्रों में उच्च टेलेंट की आवश्यकता भी है। यदि कनाडा एवं अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षित इंजीनीयर्स भारत को प्राप्त होते हैं तो यह स्थिति भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है।

उक्त कारणों के अतिरिक्त आज अन्य देशों से भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन इसलिए भी होता दिखाई दे रहा है क्योंकि, भारत में आज मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी दृष्टि से भारत का आधारभूत ढांचा आज किसी भी विकसित देश की तुलना में कम नहीं है। साथ ही, भारत में, विकसित देशों की तुलना में, मुद्रा स्फीति की दर कम होने से, सामान्य रहन सहन की लागत तुलनात्मक रूप से भारत में बहुत कम है। अत: भारत में अमेरिका एवं कनाडा की तुलना में शुद्ध बचत दर भी अधिक है। हाल ही के समय में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। आज बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में बहुत ही कम लागत पर अमेरिकी अस्पतालों की तुलना में (अमेरिका की तुलना में तो 1/10 लागत पर) अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में तो शुद्ध हवा एवं शुद्ध पानी, जो स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में सहायक होता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वरना, महानगरीय इलाकों में तो आज सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। विभिन्न देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं टेलेंटेड भारतीय जो भारत वापिस लौटे हैं, उन्होंने अपने नए प्रारम्भ किए गए स्टार्ट अप के कार्यालय दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए हैं।

भारत में बहुत लम्बे समय से मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है एवं केंद्र में एक मजबूत सरकार, उद्योग एवं व्यापार को भारत में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं व्यापार के मित्रवत आर्थिक नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में अपार वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। विकसित देशों में नागरिकों की औसत आयु 50 वर्ष से अधिक हो रही है जिससे श्रमिकों की संख्या इन देशों में लगातार कम हो रही है एवं श्रम लागत में भी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण इन देशों में उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। हाल ही के समय में चीन भी इस समस्या से ग्रसित पाया जा रहा है। केवल भारत एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों में ही श्रम लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसके कारण विश्व की कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में करना चाहते हैं। भारत में उत्पादों का निर्माण कर इन उत्पादों को विश्व के अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत में आटोमोबाईल उद्योग, मोबाइल उद्योग एवं फार्मा उद्योग इसके जीते जागते प्रमाण हैं। इन्हीं कारणों से आज भारत से कई उत्पादों का निर्यात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं भारत का विदेशी व्यापार घाटा लगातार कम हो रहा है। विदेशी व्यापार घाटे में सुधार होने के चलते भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि दृष्टिगोचर है जो हाल ही के समय में 70,000 अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को भी पार कर गया था। हालांकि, इसके बाद से इसमें कुछ गिरावट देखी गई है।

आज विश्व के कई विकसित देशों में सामाजिक तानाबाना छिन्न भिन्न हो गया है एवं इन देशों के नागरिकों में मानसिक असंतोष की भावना लगातार बढ़ रही है एवं इन देशों की आधे से अधिक आबादी आज मानसिक बीमारीयों से ग्रसित है। जबकि इसके ठीक विपरीत भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन से एवं संयुक्त परिवार की जीवनशैली के चलते भारतीय नागरिक मानसिक बीमारियों से लगभग पूर्णत: मुक्त रहे हैं एवं सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकसित देशों के नागरिकों ने भौतिक विकास तो अधिक किया है परंतु मानसिक शांति खोई है। जबकि इस धरा पर जन्म लेने का उद्देश्य ही सुखी जीवन व्यतीत करना है न कि अपने आप को मानसिक बीमारियों से ग्रसित कर देना। इन्हीं कारणों के चलते आज विश्व के कई देशों के नागरिक हिंदू सनातन संस्कृति को अपनाने की ओर लालायित दिखाई दे रहे हैं और वे भारत में बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। अत: विकसित देशों से भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन आने वाले कल की सच्चाई है।

आज का इतिहास

1899 स्पेनिश फुटबाल क्लब एफसी बार्सिलोना का गठन हुआ।
1932 सोवियत संघ और फ्रांस ने एक दूसरे पर हमला न करने की संधि की।
1947 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के लिए महात्वाकांक्षी योजना, फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश में अरब-इजरायल संघर्ष को सुलझाने के लिए, यहूदी और अरब राज्यों को अलग करने की योजना को मंजूरी देने के लिए मतदान किया।
1949 पूर्वी जर्मनी में यूरेनियम खदान में विस्फोट से 3700 लोग मरे।
1963 मॉन्ट्रियल से टेकऑफ के पांच मिनट बाद, ट्रांस-कनाडा एयरलाइन फ्लाइट 831 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 118 लोगों की मौत हो गई।
1963 कनाडा का एक जेट विमान उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
1972 अटारी ने पोंग (स्क्रीनशॉट चित्रित) जारी किया, जो कि आर्केड और होमकॉन कंसोल बाजारों में व्यापक लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले अंडरवीओ गेम में से एक है।
1972 अटारी ने पोंग को जारी किया, जो आर्केड और होम कंसोल बाजारों में लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले वीडियो गेम में से एक है।
1973 जापान के कुमामोटो शहर के क्यूशू में एक ताइयो डिपार्टमेंट स्टोर में आग लगने से 104 लोग मारे गए।
1977 पाकिस्तान के बल्लेबाज यूनुस खान का जन्म हुआ। उनके नाम 111 टेस्ट मैचों में 33 शतकों के साथ 9666 रन हैं। 265 वनडे में उन्होंने 7249 रन बनाए।
1987 कोरियाई एयर फ्लाइट 858 ने अंडमान सागर के ऊपर विस्फोट किया था जब दो कोरियन एजेंटों ने ओवरहेड डिब्बे में एक टाइम बम छोड़ा था, जिसमें 115 लोग मारे गए थे।
2005 नई क्रोएशियाई कम्युनिस्ट पार्टी की वुकोवर में स्थापना की गयी।
2005 लेसोथो सरकार अपने सभी नागरिकों को मुफ्त एचआईवी परीक्षण प्रदान करती है। एड्स के प्रसार को रोकने और पीछे लाने के उद्देश्य से, यह दुनिया में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम माना जाता है।
2006 पिछले शनिवार को बहरीन के संसदीय चुनाव के पहले दौर में इस्लामवादियों ने बड़ी संख्या में सीटें जीतने के बाद, अफवाहों के माध्यम से कहा कि शिया विपक्षी दल, अल वफ़ाक के नेता, मंत्रिमंडल फेरबदल में सरकार में शामिल होंगे।
2007 राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का स्वागत किया, उनसे आपातकालीन शासन को हटाने का आग्रह किया।

आखिर अडानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं अमेरिकी?

कमलेश पांडे

जिस तरह से दुनिया के थानेदार अमेरिका में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अदाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, उसके दृष्टिगत यह सवाल मौजूं है कि जब रिश्वत का आरोप भारत में लगाया गया है तो फिर अमेरिका में जांच कैसे शुरू हो गई? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और उसके लोग, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के चहेते उद्योगपति अडानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? क्या किसी भारतीय उद्योगपति या राजनीतिक दल के शह पर ऐसा किया जा रहा है या फिर कोई अन्य कूटनीतिक वजह है?

क्योंकि यह महज इत्तेफाक नहीं समझा जा सकता है कि पिछले साल 2023 में अमेरिकी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद अब वर्ष 2024 में अदाणी समूह पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का उछला ताजा मामला एक अदद मामला भर है? वजह यह कि इससे अडानी समूह के शेयरों के भाव गिरते हैं और कम्पनी को काफी क्षति उठानी पड़ती है! इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि आखिर में यह मामला क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है? और अंत में, इसका समुचित हल क्या है? आइए इस पूरी बात को क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।

बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने अदाणी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (2200 करोड़ रुपए से ज्यादा) की रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जो एक गम्भीर बात है। क्योंकि यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप में कहा है कि अदाणी ने अपनी कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकायों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी है।

मसलन, अदाणी पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद राज्य सरकार 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने पर सहमत हुई थी। आंध्र के अधिकारियों को 25 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से कथित रिश्वत दी गई। इसके अलावा, अमेरिकी सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। खास बात यह है कि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इंवेस्टर्स से छिपाया है, जिनसे अदाणी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे।

लिहाजा, अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। बता दें कि अडानी समूह ने साल 2021 में एक बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनैशनल इंवेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया है। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने बयान में कहा है कि कथित साजिश के तहत अदाणी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए और एज्यूर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में लिस्टेड किया। साथ ही, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अदाणी, सागर अदाणी, सिरिल कैबनेस और अदाणी ग्रीन और एज्यूर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं।

वहीं, अदाणी ग्रुप ने रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया है। उसने कहा है कि ग्रुप सभी कानूनों का पालन करता रहा है। वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। ग्रुप के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्याय विभाग के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया जिसका अडानी पर यह केवल आरोप है और जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाएगा। लिहाजा, बयान में कहा गया कि हम आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन है। अदाणी ग्रुप ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लि. के 60 करोड़ डॉलर के बॉण्ड को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में ठेका मिला है।

ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल है कि जब भारत में रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं तो फिर केस यूएस यानी अमेरिका में क्यों? इसका जवाब यही है कि अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। चूंकि, प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है, इसलिए अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ।

चूंकि अमेरिका भारत का मित्र देश भी है, इसलिए ये आरोप अहम हैं। हालांकि, जिस तरह से अमेरिकी चुनावों में परास्त राष्ट्रपति जो बाइडेन के मातहत प्रशासन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने और भारत के उद्योगपति को भ्रष्टाचार के मामले में उलझाने की पहल जाते-जाते की है, इसके अंतर्राष्ट्रीय सियासी मायने को भी समझने की जरूरत है। शायद वह भावी ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहता हो।

सवाल यह है कि आखिर यह हंगामा किन-किन प्रोजेक्ट्स को लेकर मचा है? तो जवाब यही होगा कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार, एनर्जी कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदाणी है। अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी है, जो उनके भतीजे हैं। इसके अलावा, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्यूअर हैं।

हुआ यह है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी इश्यूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था।

हालांकि, एसईसीआई को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। लिहाजा खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इसलिए अदाणी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। तो फिर यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर में रिश्वत का हिस्सा किनको किनको मिला? उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा किनको मिला? इसके जवाब भी अमेरिकी प्रशासन के आरोपों से मिलते हैं।

अमेरिकी प्रशासन के आरोपों के मुताबिक, इन लोगों ने तय किया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को एसईसीआई के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। शायद इसलिए उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। फलाफल यह निकला कि इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियां सहमत हुईं और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए एसईसीआई के साथ समझौता किया।

इससे साफ है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय (न्यू यॉर्क) के अनुसार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें गौतम एस. अदाणी, सागर एस. अदाणी, विनीत एस. जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल के नाम प्रमुख हैं।

हालांकि, अमेरिकी कानूनों के तहत ऐसे मामलों में आमतौर पर डेफर्ड प्रॉसिक्यूशन एग्रीमेंट्स या नॉन प्रॉसिक्यूशन एग्रीमेंट्स के जरिए सेटलमेंट की इजाजत है। जिसके मुताल्लिक कुछ गलतियां स्वीकार करने, नियमों का अनुपालन बेहतर करने के वादे और जुर्माना चुकाने के साथ ही यह मामला सुलझाया जा सकता है। इससे पहले भी सीमेंस ने 80 करोड़ डॉलर और एरिक्सन ने 1 बिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाया था। लिहाजा, अदाणी ग्रुप भी चाहे तो ऐसा कुछ कर सकता है।

कहना न होगा कि हिंडनबर्ग मामले के चलते अमेरिका में अदाणी ग्रुप की कंपनियों का बाजार मूल्य जितना घटा था, उससे दोगुनी गिरावट अमेरिकी अदालत में ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी पर लगे आरोपों के चलते आई है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला ग्रुप की साख के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन अमेरिका में इस मामले के निपटारे के रास्ते भी की कंपनियों के शेयर इस गिरावट से जल्द उबर सकते हैं, हालांकि निवेशकों को फिलहाल सेटलमेंट की गुंजाइश चुनिंदा है।

सवाल है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की संभावित नीतियों, चीन में राहत पैकेज और रूस-यूक्रेन संकट गहराने और इजरायल-फिलिस्तीन विवादों के बढ़ते चले जाने के चलते भारतीय शेयर बाजार में पहले से ही कमजोरी दिख रही थी। फिर, अडाणी मामले ने इसे और हिला दिया। अलबत्ता, ताजा मामले का इस ग्रुप पर जैसा भी असर पड़े, लेकिन इतना तय है कि देश की इकॉनमी पर आंच नहीं आने जा रही। भारत में लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था का दमखम, कंपनियों के मुनाफे में अच्छी बढ़त और रेगुलेटरी साख ही शेयर बाजार के लिए अहम है। ऐसे में भारत पर दांव लगाने वाले विदेशी निवेशक इन चीजों को नजरंदाज नहीं करने जा रहे।

इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि जब भी भारत में संसद सत्र शुरू होने वाला होता है तो भारत के प्रतिपक्ष को अमेरिका एक नया मुद्दा थमा देता है। अब जबकि सोमवार 25 नवम्बर से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो यह नया मामला सामने आ गया। लिहाजा, उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग की। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष के नाते वह और पूरा विपक्ष अदाणी से जुड़े मामले को उठाएगा।

बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अदाणी पर लगे आरोपों पर कहा कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि गौतम अदाणी की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और वह एक हैं और इसीलिए दोनों सेफ हैं। यह राजनीतिक, वित्तीय और अफसरशाही से जुड़े लोगों का पूरा नेटवर्क है। एक तरफ ये नेटवर्क देश के राजनीतिक तंत्र को कब्जे में करता है, दूसरी तरफ मुनाफे का काम करता है। इसलिए सेबी चीफ माधवी पुरी बुच को पद से तुरंत हटाकर जांच हो।

वहीं, कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद व प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2002 से ही नरेन्द्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए है।

लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा में हेमंत अव्वल

आशुतोष चतुर्वेदी

झारखंड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को राज्य की बागडोर सौंप दी है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि झारखंड गठन के बाद पहली बार कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है। हेमंत सोरेन को जनता ने ऐसा बहुमत सौंपा है, जो इसके पहले किसी अन्य गठबंधन को हासिल नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी समुदाय और हाशिए पर छूटे लोगों ने हेमंत सोरेन पर पूरा भरोसा जताया है। उनकी जीत में मंईयां योजना, बिजली बिल माफी और कृषि ऋण माफी का असर भी नजर आता है। हेमंत सोरेन से जनता की भारी अपेक्षाएं हैं और उनके समक्ष इन पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। जनता की अपेक्षा है कि हेमंत सोरेन प्रभावी और साफ सुथरा प्रशासन देंगे। जल, जंगल, जमीन में झारखंड की आत्मा बसती है, उनके सामने इसे सहेजने का अवसर है। इस बार विपक्ष खास कर भाजपा बहुत कमजोर है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। उम्मीद है कि विपक्ष राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। यह हम सब जानते हैं कि आज झारखंड को जहां होना चाहिए था, वह वहां नहीं है। 24 साल में विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, वैसी नहीं रही है। लोगों को उम्मीद है कि हेमंत झारखंड के विकास को नयी रफ्तार देंगे। आम आदमी की तीन बुनियादी जरूरतें हैं- बिजली, पानी और सड़क। इन तीनों क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना बाकी है। प्रकृति झारखंड पर मेहरबान रही है। प्रकृति ने इतना खनिज देश के किसी अन्य राज्य को नहीं दिया है। इन खनिजों का दोहन तो होता है, लेकिन इसका पूरा लाभ न तो राज्य को मिल पाता है और न ही यहां के लोगों को। इन खनिजों पर आधारित उद्योग झारखंड में लगे, तभी राज्य को लाभ मिल पाएगा। झारखंड के बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम करना होगा। झारखंड में सब्जी-फलों की अच्छी खेती होती है। यहां की सब्जी कोलकाता और मुंबई तक जाती है। पर इसका लाभ किसानों को न मिलकर बिचौलियों को मिलता है। कोल्ड स्टोरेज हों, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगें, तो किसानों का भाग्य बदल जायेगा। दो और अन्य क्षेत्र हैं-शिक्षा और स्वास्थ्य। राज्य के लोगों को पढ़ाई और चिकित्सा के लिए दक्षिण भारत जाना पड़ता है। अगर झारखंड को ही हेल्थ और एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाये, तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है।

हरियाणा के बाद महाराष्ट्र ने दी भाजपा को ऊंची उड़ान

राजकुमार सिंह

लोकसभा चुनाव में खराब मौसम में फंसते दिखे भाजपा के चुनावी विमान को हरियाणा के बाद महाराष्ट्र ने जो ऊंची उड़ान दी है, उसके सदमे से उबर पाना विपक्षी गठबंधन 'इंडिया', खासकर कांग्रेस के लिए संभव नहीं लगता। लोकसभा चुनाव परिणाम में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति पर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी भारी पड़ता नजर आया था। लोकसभा चुनाव में लगभग एक-तिहाई सीटों पर सिमट जाने के बावजूद महायुति के लिए संतोष की बात थी कि विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त के मामले में फासला ज्यादा नहीं था।

मत प्रतिशत में भी ज्यादा अंतर नहीं था इसीलिए महायुति ने हिम्मत हारे बिना जमीनी राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन की बिसात बिछाई और हारी हुई लग रही बाजी पलट दी। अक्सर हार के बाद ईवीएम समेत चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठानेवाले विपक्ष ने फिलहाल तो समीक्षा और आत्मविश्लेषण की बात ही कही है। दरअसल यह विपक्ष के लिए समीक्षा से भी

ज्यादा आत्मविश्लेषण की घड़ी है।

आखिर कुछ तो कारण हैं कि विपक्ष जीती दिख रही बाजी भी हार जाता है और भाजपा या उसके नेतृत्ववाला गठबंधन हारी हुई दिख रही बाजी भी जीत जाता है। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस ने 10 में से पांच-पांच लोकसभा सीटें जीतीं। राजनीतिक प्रेक्षक भी मानने लगे कि भाजपा के हाथ से हरियाणा की सत्ता फिसलने ही वाली है, लेकिन महज चार महीने बाद ही पासा पलट गया।

भाजपा ने पिछली दोनों बार से भी ज्यादा सीटें जीतते हुए शानदार 'हैट्रिक' की। महाराष्ट्र तो हरियाणा से भी दो कदम आगे निकल गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा की महायुति महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा के हिस्से तो मात्र नौ सीटें ही आई थीं। जिस तरह इस बार हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए।

लोकसभा चुनावों के बाद से लोक-लुभावन योजनाओं और घोषणाओं की झड़ी लगा दी गई, उससे भी संकेत यही गया कि भाजपा को सत्ता की जंग की मुश्किलों का अहसास है। चुनावी मुद्दे कमोबेश समान होने के बावजूद झारखंड में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की जीत महाराष्ट्र के जनादेश के विश्लेषण को और भी मुश्किल बना देती है।

भाजपा की हरसंभव कवायद के बावजूद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राजद-वाम दल सरकार को लगातार दूसरी बार जनादेश राजनीतिक दलों और नेताओं की विश्वसनीयता पर भी विचार की जरूरत को रेखांकित करता है। अपने पांच साल के शासन में आदिवासी बहुल झारखंड में गैरआदिवासी मुख्यमंत्री पर दांव लगानेवाली भाजपा का पूरा फोकस इस बार आदिवासी राजनीति पर रहा, लेकिन मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत पाई। निश्चय ही महाराष्ट्र और झारखंड के जनादेश का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि मतदाताओं ने स्थिर सरकार के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है।

लेकिन दोनों ही राज्यों के मतदाताओं ने जनादेश के साथ आनेवाली सरकारों पर जन आकांक्षाओं का जो बोझ डाला है, उसकी कसौटी पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। लोक-लुभावन योजनाएं और घोषणाएं मतदाताओं को आकर्षित करने में निश्चय ही सफल रहती हैं, लेकिन जनआकांक्षाओं पर खरा न उतरने पर होनेवाली जन प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र होती है। पहले से ही अर्थव्यवस्था पर दबाव झेल रहे महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों को राजनीति और अर्थनीति के बीच संतुलन बिठाने की मुश्किल कवायद की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा।

फिर बना पिछले आम चुनाव से पहले वाला सीन

राहुल वर्मा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो जोश और रहस्य बना हुआ था, नतीजों ने उस पर पानी फेर दिया। शनिवार को जब रिजल्ट आए तो पता चला कि वहां महायुति अलायंस के पक्ष में एकतरफा माहौल था। नतीजों से पहले एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यह भी कहा जा रहा था कि निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों के साथ जिलास्तर के राजनीतिक क्षत्रप तय करेंगे कि महायुति और महाविकास आघाड़ी (एमवीए) में किसका पलड़ा भारी साबित होगा।

राज्य में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के महायुति गठबंधन ने कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एमवीए अलायंस को जबरदस्त शिकस्त दी। यही नहीं, 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति तीन चौथाई बहुमत से भी आगे निकलने में सफल रहा। उसका वोट शेयर भी एमवीए से दहाई अंकों में अधिक है।

इस चुनाव से पहले हुए किसी भी अलायंस को राज्य में ऐसी धमाकेदार जीत नहीं मिली थी। भाजपा ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे पहले 2014 में उसने सबसे अधिक 122 सीटें जीती थीं। दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए यह महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा।

2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली थी। उसके बाद पार्टी ने जाहिर कर दिया था कि वह राज्य में शिवसेना के पीछे चलने के मूड में नहीं है। इससे भाजपा और शिवसेना के अलायंस में दरार आई। 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया और 122 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन तब वह बहुमत से चूक गई थी।

खैर, उसने तब गठबंधन सरकार बनाई और 2019 विधानसभा चुनाव फिर से शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा। मुख्यमंत्री पद किस पार्टी को मिलेगा, तब इसे लेकर दोनों के बीच तकरार हुई और शिवसेना उसके बाद कांग्रेस-एनसीपी के पाले में चली गई। फिर शिवसेना और एनसीपी के टूटने से राज्य की सियासत कई धड़ों में बंट गई। इससे राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों

में बदलाव आया। खैर, इन नतीजों ने यह संकेत दे दिया है कि आगे महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा क्या होगी।

यहां सवाल यह है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? पहली नजर में देखने पर यह कहा जा सकता है कि महायुति के पीछे महिला वोटरों के गोलबंद होने का यह नतीजा है। लाडकी बहिण योजना को इसका क्रेडिट दिया भी जा रहा है। लेकिन किसी एक मुद्दे की वजह से ऐसे एकतरफा नतीजे नहीं आया करते। ऐसा लगता है कि महायुति सरकार ने चुनाव से पहले सभी सही कदम उठाए।

दूसरी ओर, एमवीए के लिए जो भी गलत हो सकता था, वह हुआ। एमवीए के सहयोगी दलों को सीट बंटवारे में मुश्किल हुई। जीतने पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसे लेकर भी उनके बीच खटपट थी। टिकट बंटवारे में गलती के आरोप भी लगे। कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर सहयोग न होने जैसी बातें भी सामने आईं। यह भी कहा गया कि मनी पावर में महायुति एमवीए से मुकाबला नहीं कर पाया।

बहरहाल, एक्सिस-माय इंडिया ने एग्जिट पोल में महायुति की एकतरफा जीत का दावा किया था, जो सही निकला। उसने कहा था कि महिला वोटरों के बीच महायुति काफी लोकप्रिय है। लेकिन यह भी मानना होगा कि इस अलायंस को कई सामाजिक-आर्थिक वर्गों से जबरदस्त समर्थन मिला। मुस्लिम और दलितों को छोड़ दें तो दूसरे सभी वर्गों में महायुति को बढ़त मिली। जहां अनुसूचित जनजाति, मराठा और कुनबी समाज में उसे एमवीए की तुलना में मामूली बढ़त मिली, वहीं ओबीसी और सवर्णों के बीच उसे एमवीए की तुलना में दोगुने से भी अधिक वोट मिला। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जिन एकनाथ शिंदो को जिलास्तर का क्षत्रप माना जाता था, उनकी इन चुनावों से पहले रेटिंग देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे से अधिक थी।

इन नतीजों का राज्य और देश की राजनीति पर क्या असर होगा? पहला, इन दोनों अलायंस से बाहर जो दल हैं, वे हाशिये पर चले गए हैं। इसका संकेत पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनावों में मिला था। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में निर्दलीयों और छोटी पार्टियों को 25 प्रतिशत वोट और 29 सीटें मिली थीं। इन चुनावों में उनका वोट शेयर और सीटों की संख्या तब से आधी रह गई है। इसलिए मुमकिन है कि ये पार्टियां और ऐसे नेता अब दोनों में से किसी अलायंस का दामन थाम लें।

दूसरा, यह देखना अभी बाकी है कि दोनों में से कौन सी शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाती है क्योंकि ठाकरे परिवार का रुतबा इन नतीजों के बाद घटा है। राज ठाकरे की एमएनएस तो पहले से हाशिये पर है, उद्धव धड़े का स्ट्राइक रेट पिछले लोकसभा चुनावों में भी खराब रहा था। अगर उद्धव की पार्टी का प्रदर्शन बीएमसी चुनावों में भी खराब रहता है तो जो प्रत्याशी जीते हैं, उन्हें भी साथ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इन नतीजों का शरद पवार के परिवार के लिए क्या संकेत है? अजित पवार धड़े के अच्छे प्रदर्शन के बाद इसे लेकर कई संभावनाएं बन गई हैं। देखना होगा कि क्या परिवार के दोनों धड़ों के बीच कोई समझौता होता है?

तीसरा, पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस फिर से राष्ट्रीय स्तर पर बुरी स्थिति में पहुंच गई है। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत में भी इसकी भूमिका अहम नहीं रही है। न ही कुछ महीने पहले जम्मू-कश्मीर में हुए चुनावों में अलायंस की जीत में उसका बड़ा रोल था। पहले हरियाणा और उसके बाद अब महाराष्ट्र में हार के बाद लगता है कि कांग्रेस बुनियादी चुनौतियों से जूझ रही है। उसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिए। दूसरी ओर, दोनों राज्यों में जीत से भाजपा राहत की सांस ले सकती है, लेकिन उसे भी इस बारे में सोचना होगा कि झारखंड में पार्टी की हार क्यों हुई, जहां वह सत्ता में लौटने की उम्मीद पाले हुई थी।

चुनावी रेवड़ियों से लोकतंत्र का कितना भला होगा?

विश्वनाथ सचदेव

किसको किसने कितनी रेवड़ियां बांटीं, यह सवाल भले ही किसी लंबी-चौड़ी गणना की अपेक्षा करता हो, पर यह बात सब मान रहे हैं कि हाल के चुनावों में खूब रेवड़ियां बंटीं। नहीं, मैं चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाता को चुपचाप बांटे जाने वाले रुपयों की बात नहीं कर रहा, मैं बात उन रेवड़ियों की कर रहा हूं जिन्हें बांटने वाले लंबी-चौड़ी घोषणाओं के साथ बांटते हैं। चुनाव-परिणाम का विश्लेषण करने वाले जिस एक बात पर सहमत दिखाई देते हैं वह यह है कि इन रेवड़ियों ने परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डाला है।

यह रेवड़ियां बांटना कोई नई बात नहीं है। शायद इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य की लड़कियों को साइकिलें बांटने से हुई थी। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो बिजली, पानी आदि मुफ्त बांटकर जैसे एक नई परंपरा ही शुरू कर दी थी रेवड़ियां बांटने की। बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में तो यह काम प्रतिस्पर्धा की तरह हुआ।

ऐसा नहीं है कि इस 'मुफ्तखोरी' की आलोचना नहीं हुई। मतदाता को आर्थिक सहायता देने की इस प्रथा की आलोचना स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। शायद इस तरह मतदाता को रिझाने की कोशिश को रेवड़ियां बांटने की संज्ञा भी उन्होंने ही दी थी। यूं तो चुनाव घोषणापत्रों में जो वादे किए जाते हैं, उन्हें भी मतदाता को दी जाने वाली रिश्वत कहा जा सकता है, पर नगद राशि बांटने को किसी और तरह से नहीं समझाया जा सकता। रेवड़ियां बांटने वाले इस रिश्वत को कल्याणकारी राज्य के अनुरूप आचरण बताते हैं।

हम भले ही आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने का दावा करते हों, पर इस हकीकत से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि आज हमारे देश की अस्सी प्रतिशत आबादी को सरकार की ओर से मुफ्त अनाज देकर उसका पेट भरा जा रहा है। यह तथ्य यही बताता है कि गरीबी हटाओ के सारे दावों और वादों के बावजूद आज भी स्वतंत्र भारत का नागरिक अपने श्रम से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने लायक नहीं बन पाया है। आजादी के शुरुआती सालों में तो यह बात फिर भी समझ आती थी कि नया देश नई चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है।

हालात सुधारने में वक्त लगेगा, पर आजाद होने के सत्तर-अस्सी साल बाद भी यदि देश की जनता रेवड़ियों से रिझाई जा सकती है तो इसका सीधा-सा मतलब यही है कि हमारी नीतियों-रीतियों में कहीं कुछ गंभीर गड़बड़ है। हमारी त्रासदी यह भी है कि गड़बड़ी का पता लगाने और उसे ठीक करने की ईमानदार कोशिश करने के बजाय हम रेवड़ियां बांटकर कर काम चलाना चाहते हैं।

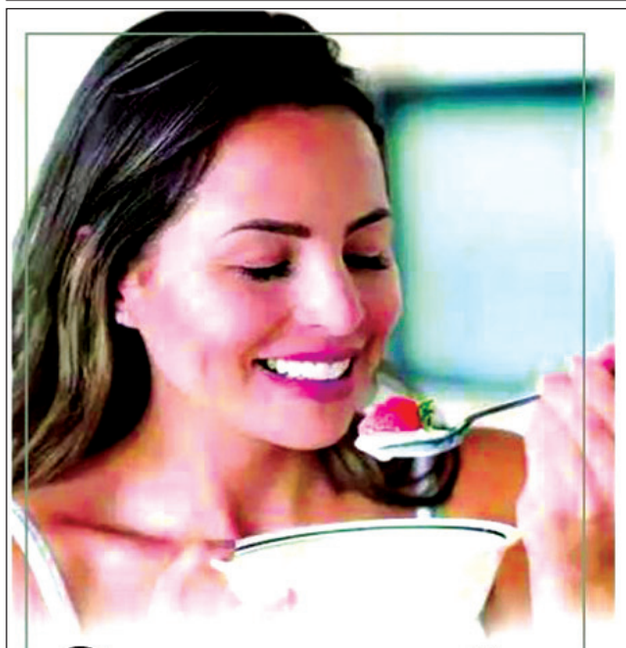

कितना सही है नाश्ते में दही लेना

नाश्ते में हम सभी कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं, जो खाने में टेस्टी हो और हमारे शरीर को पूरा दिन काम करने की एनर्जी देता रहे। ऐसे में ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में नाश्ते में दही खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या नाश्ते में दही लेना एक स्वस्थ विकल्प है?

पाचक होती है लेकिन नींद दिलाती है

- यदि आपके दिन शुरुआत ही दही के साथ हो रही है तो यह आपको एनर्जी देने के स्थान पर नींद दिला सकती है और शरीर में सुस्ती बढ़ा सकती है। इसलिए दही कभी भी आपके फर्स्ट फूड का भाग नहीं होना चाहिए। हालांकि दही नाश्ते का एक शानदार हिस्सा है। यदि आप इसे खाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तब.

समझे विरोधी बातों का अर्थ

- एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि दही नाश्ते में खाना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि इसे खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। दरअसल, ये दोनों ही बातें सही हैं। दही खाने पर आपको एनर्जी मिलेगी या सुस्ती आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दही खाने का आपका तरीका क्या है।

इस तरह खाएं और इस तरह ना खाएं दही

- आप नाश्ते में चपाती, पराठा, चिल्ला आदि के साथ दही खा सकते हैं। एक कटोरी दही का सेवन नाश्ते में करना शरीर के लाभकारी होता है और पाचनतंत्र को सही करता है। साथ ही शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा देने में लाभकारी होता है।
- लेकिन नाश्ते में दही का सेवन तभी करना चाहिए जब आप सुबह के समय नाश्ते से पहले कुछ खा या पी चुके हों। जैसे, सुबह की शुरुआत आपने पानी के साथ की हो और फिर चाय-टोस्ट, स्प्राउट्स या ड्राईफ्रूट्स आदि खाए हों। इसके एक घंटे बाद यदि आप नाश्ते में दही का सेवन करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको गैस बनने की समस्या है तो इन 5 सब्जियों से बचना चाहिए

खाली पेट नहीं खानी चाहिए दही

- सुबह के समय आप नाश्ते में केवल मीठी दही का उपयोग कर सकते हैं। खट्टी दही खाने से परहेज करें। साथ ही नाश्ते में दही खाते समय आप इसमें एक चम्मच शक्कर मिला सकते हैं। यदि आपको शुगर की समस्या नहीं है तब।
- दिन की शुरुआत यदि किसी भी कारण देरी से हुई हो और आपके पास नाश्ता करने का समय ना हो तो भूलकर भी खाली दही ना खाएं। यदि आप खाली पेट दही खाते हैं तो आपको जबदस्त नींद आएगी और आप खुद को बहुत थका हुआ अनुभव करेंगे।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाली पेट दही खाने से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या हो जाती है। इससे शरीर में ब्लड का फ्लो कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। यही कारण है कि बहुत तेज नींद आती है और बेहोशी जैसा अनुभव होता है।

लगातार बनी रहती है थकान तो ऐसे रखें अपना ध्यान

आप चाहे मानसिक काम अधिक करते हैं या शारीरिक काम। यदि आपको काम करते समय बहुत जल्दी थकान होने लगती है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है। जी हां, केवल पोषण की कमी के कारण ही नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी के कारण भी जल्दी थकान होती है। जो लोग नियमित रूप से जरूरी पानी नहीं पीते हैं, उन्हें काम करते समय अधिक थकान होना और अन्य लोगों की तुलना में जल्दी थकान होने जैसी समस्याएं होती हैं। जानें, जल्दी थकान होने के अन्य कारण और उनके निवारण के तरीके

जल्दी थकने की वजह

- आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी थकान होने की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में कुछ खास तत्वों की कमी देखने को मिलती है.
- पानी की कमी
- खून की कमी
- विटमिन-बी12 की कमी
- फोलेट या फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है।

जल्दी थकान से बचने के तरीकों में ना केवल अपने खान-पान पर ध्यान देना है बल्कि यह भी ध्यान देना है कि जिस डायट का सेवन आप कर रहे हैं और जिन ड्रिंक्स को आप ले रहे हैं, क्या वे आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यहां जानें कैसे रखा जाएगा इस बात का ध्यान.

तरल पदार्थों का सेवन

- जल्दी-जल्दी होने वाली थकान की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। इनमें जूस, सूप, छांछ, दाल इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही समय-समय सादा पानी पीते रहें। वयस्कों को हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए।

तनाव को नियंत्रित करना सीखें

- जल्दी थकने की एक बड़ी वजह लगातार बना रहनेवाला तनाव भी होता है। तनाव का कारण चाहे जो भी लेकिन यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द थका देता है। इसलिए तनाव से

बचने के लिए हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। यह आपको मानसिक रूप से फिट रखने का काम करेगा।

फलियों का सेवन करें

- हरी फलियां कई तरह की वरायटी में आती हैं। खास बात यह है कि मौसम की प्रकृति और उस दौरान शरीर की जरूरत के अनुसार हर सीजन में आनेवाली फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।
- हरी फलियां फाइबर युक्त होती हैं और इनका पाचन धीमी गति से होता है। इसलिए ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम करती हैं, जिससे शरीर पर थकान कम हावी होती है।

ड्राईफ्रूट्स

- ऐसा नहीं है कि ड्राईफ्रूट्स का सेवन केवल सर्दियों में ही करना चाहिए। बल्कि सीमित मात्रा में और दूध के साथ ड्राईफ्रूट्स का सेवन गर्मियों में भी हर दिन किया जा सकता है।
- क्योंकि ड्राईफ्रूट्स केवल हमारे शरीर को गर्माहट देने का ही काम नहीं करते हैं बल्कि पोषण देने का काम भी करते हैं। शरीर की कमजोरी को दूर करने में मीट भी अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में हम आपको मीट खाने की सलाह नहीं देना चाहते हैं। इस समय में आप थकान से बचने के लिए ड्राईफ्रूट्स यानी सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण

शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना कई रोगों का कारण बनता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर सबसे जल्दी और सबसे बुरा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण क्या होते हैं.

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से अर्थ है कि शरीर को अपनी नियमित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाना।
- जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले व्यक्ति को थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती या सांस फूलने लगता है। इसके बाद शरीर में रक्त के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। इससे थकान और घबराहट बढ़ जाती है।

हो सकती हैं ये बीमारियां

- यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है।
- ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायरॉइड हॉर्मोन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायरॉइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ सकता है या बहुत अधिक घट सकता है।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कई कारण होते हैं, जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। जो लोग बहुत अधिक आलस से भरपूर जीवनशैली जीते हैं यानी फिजिकल ऐक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं लेकिन उसके हिसाब से डायट नहीं लेते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
- जिन लोगों के भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते रहें तो उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्योंकि फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चैन की नींद सोना है तो जरूर करें यह काम

अगर आप चाहते हैं कि रात में आपको सुकून की नींद आए, पैरों में कुलन और बेचैनी के कारण आपकी नींद में किसी तरह की बाधा ना आए तो आपको सोने से पहले एक खास काम करना होगा। यह काम आपके शरीर को राहत देने के साथ ही दिमाग को भी शांति देगा। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या और कैसे करना है.

आपको क्या करना है ?

- बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने पैर साफ पानी से धुलकर कॉटन के कपड़े से पोछकर साफ करने हैं। इसके बाद सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करें। यह मालिश 2 से 3 मिनट की भी हो तो काफी है। यहां जानें इस तरह हर दिन मालिश करने से आपको किस तरह के लाभ होंगे.

पैर के तलुए में होते हैं सभी एक्युप्रेशर पॉइंट्स

- हमारे पैर के तलुओं में पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पैर के तलुओं पर मसाज करने से इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसलिए आप अच्छी नींद आती है।

ताउम्र रहेंगे युवा

- अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने पैर के तलुओं पर सरसों के तेल से मालिश करेंगे तो आप ताउम्र युवा बने रहेंगे। यहां युवा बने रहने से हमारा आशय है कि आपके दांत, आपकी दृष्टि और आपके शरीर के जोड़ों में किसी तरह का दर्द या समस्या नहीं हो पाएगी।

चश्मा नहीं लगेगा

- यदि आप सोने से पहले हर दिन अपने पैरों पर सरसों तेल से मालिश करते हैं तो आप अपनी कमजोर आइसाइट को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो हफ्ते में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा।

पाचन को ठीक रखे

- आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। लेकिन यह सही है कि जो लोग नियमित रूप से अपने पैर के तलुओं पर मालिश करते हैं या किसी और से कराते हैं, उनका पाचनतंत्र अन्य लोगों की तुलना में काफी ठीक रहता है। साथ ही उन्हें पेट संबंधी रोग नहीं घेरते हैं।
- साथ ही ऐसे लोगों के शरीर पर थकान हावी नहीं हो पाती है। पैर के तलुओं की मसाज करने से शरीर के डैमेज सेल यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जल्द मरम्मत होती है। इससे त्वचा भी चमकदार बनी रहती है। तो देर किस बात की, खूबसूरती और सेहत के लिए आज से ही शुरू करें पैर के तलुओं की मालिश।

ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत हो सकता है आंखों में पानी आना

आंखे शरीर का सबसे जरूरी, सुंदर और नाजुक अंग है। सर्दी के मौसम में नमी और ठंडक के कारण आंखों में पानी आ जाता है लेकिन यह ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है। इस बीमारी में आंखों से बहुत ज्यादा पानी आना, धुंधला दिखाई देना और चुभन महसूस होना, सूजन, रैशेज, लालपन जैसे लक्षण दिखाई देते है। इस बीमारी का समय पर इलाज न करने पर आंखों की रोशनी जा भी सकती है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की दवाइ के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप बिना किसी नुकसान के इस परेशानी से छुटकारा पा सकते है।

गीला कपड़ा - आंखों को हाथों से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में जलन, दर्द या खुजली होने पर साफ पानी में कपड़े को भिगोकर आंखों की सफाई करें। इससे किसी भी तरह की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।

नारियल का तेल - नारियल तेल में मौजूद गुण आखों की गंदगी को साफ करते हैं। रोजाना आंखों के नीचे और आस-पास नारियल के तेल की मालिश करें। आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा।

हर्बल टी - कोमोमाइल या पेपरमिंट चाय की पत्तियों को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों की सिकाई करें। ध्यान रहें कि पानी ज्यादा गर्म न हो।

नमक - कई बार आंखो में जलन और खुजली के कारण पानी आने लगता है। ऐसे में आप 1 गिलास गर्म पानी में चुटकीभर नमक डालकर आंखों की सिकांई करें। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल खुजली और जलन की परेशानी को दूर कर देगा।

बेकिंग सोडा - साफ पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर गर्म करें। पानी थोड़ा रह जाने पर इससे अपनी आंखों को धो लें। इससे आपको आराम मिल जाएगा।

ठंडा दूध - कॉटन बॉल को ठंडे दूध में डिप करके अपनी आंखों के आस-पास रगड़ें। इसके अलावा आप कॉटन बॉल को ठंडे दूध में भिगोकर रख भी सकते है। इन उपायों को सुबह-शाम करने से आपको आराम मिल जाएगा।

एलोवेरा - एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद और 1/2 कप एल्डरबैरी चाय मिलाएं। रोजाना दिन में 2 बार इस मिश्रण से अपनी आंखों को धोएं। आपकी परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी।

कच्चा आलू - एस्ट्रिंजेंट के गुणों से भरपूर कच्चा आलू आंखों में पानी आने की समस्या से जल्दी राहत देता है। आलू की पतली स्लाइस काट कर कुछ देर फ्रिज में रखें। इसके बाद इस ठँडी स्लाइस को 15 से 20 मिनट के लिए आंखों के उपर रख लें। 2-3 दिन तक इसका इस्तेमाल आपकी इस समस्या को दूर कर देगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

वायनाड से जीत के बाद प्रियंका ने सांसद के रूप में शपथ ली

नईदिल्ली। केरल के वायनाड से जीतने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली और केरल कसावु साड़ी पहनी, जो मलयाली उत्सवों में आम तौर पर सुनहरे बॉर्डर वाली एक प्रमुख ऑफ-व्हाइट साड़ी होती है। उनकी पोशाक वायनाड में सक्रिय रूप से काम करने का एक सूक्ष्म संकेत लग रही थी। हाथ में संविधान की किताब लिए 52 वर्षीय प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसद में बैठे सांसदों की मौजूदगी में शपथ ली। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे, और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे निचले सदन की गैलरी में मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में प्रवेश के साथ, संसद में अब दशकों में पहली बार गांधी परिवार के तीन सदस्य हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जहां लोकसभा में बैठेंगे, वहीं उनकी मां सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का विकल्प चुनने के बाद राज्यसभा में हैं।

ममता ने वक्फ विधेयक को बताया धर्मनिरपेक्ष विरोधी

कोलकाता। विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे संघीय और धर्मनिरपेक्ष विरोधी बताया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक एक विशेष वर्ग के लिए है। उनका कहना है कि वक्फ विधेयक के जरिए मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने वक्फ विधेयक पर उनसे बातचीत नहीं की। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, इस विधेयक को लेकर हमारे साथ कोई चर्चा नहीं की गई। यह वक्फ की संपत्ति को नष्ट कर देगा। वे ऐसा विधेयक क्यों लेकर आए, जो एक धर्म के खिलाफ है। यह एक संघीय विरोधी विधेयक है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी धर्म पर हमला किया गया तो वह इसकी निंदा करेगी। विपक्षी दलों ने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की तीखी आलोचना की।

वक्फ संशोधन विधेयक समिति का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित समिति का कार्यकाल बजट सत्र 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ाया गया। लोकसभा ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। बता दें कि समिति की बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। समिति को इस सप्ताह के अंत तक रिपोर्ट देनी थी। मामले में समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि समिति के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे समय से सदन को भेजा जाएगा। हालांकि विपक्ष को इस पर आपत्ति थी। विपक्ष समिति का कार्यकाल बढ़वाना चाहता था। इस संबंध में विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। बुधवार को समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया।

महा विकास अघाड़ी से अलग नहीं होगी उद्धव सेना : राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने गुरुवार को पुष्टि की कि महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत के बाद विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में कोई दरार नहीं है। उन्होंने अफवाहों को निराधार बताया और पुष्टि की कि उद्धव सेना एमवीए नहीं छोड़ रही है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व वाला गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों में एक साथ लड़ने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अगर कोई यह (अफवाह) कहता है, तो यह उनकी निजी राय हो सकती है। जब हम आम चुनाव जीते थे, तो किसी ने नहीं कहा कि उद्धव सेना को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग चिंतित क्यों हैं? अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं... हम देखेंगे, हमें पता है कि क्या करना है।

शपथ लेने के बाद हेमंत जारी करेंगे मंईयां सम्मान की राशि

रांची। झारखंड सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद दिसंबर से राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 25-25 सौ रुपये भेजने की तैयारी समाज कल्याण विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नवंबर माह में सबके खाते में राशि भेज दी गयी है। अधिकारियों ने कहा कि योजना के तहत निबंधन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। दिसंबर महीने में 57 लाख से अधिक महिलाओं की संख्या योजना के लाभुक के रूप में हो सकती है। विभाग द्वारा यह तैयारी चल रही है कि 11 दिसंबर तक सबके खाते में राशि चली जाये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई कैबिनेट की बैठक में मंईयां सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने का प्रावधान कर दिया था। इसमें कहा गया था कि दिसंबर माह से प्रत्येक महिला के खाते में 25-25 सौ रुपये भेजे जायेंगे। अभी वर्तमान में 1000 रुपये दिये जा रहे हैं।

...जब राज्यसभा में प्रमोद तिवारी को जगदीप धनखड़ ने दी सलाह

नईदिल्ली। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच राज्यसभा की कार्यवाही के लगातार स्थगित होने के बाद, उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को हंगामा करने और सार्थक बातचीत का अवसर चूकने पर सांसदों को समझाया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की बैठक दोबारा होगी। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर हुए हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन उस रचनात्मक भागीदारी से चूक गया जो लोगों की सामूहिक आकांक्षा को प्रतिध्वनित करती।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के एक सवाल पर हम आसन को कैसे मना सकते हैं? इसके जवाब में जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम ऐतिहासिक रूप से नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानक का प्रदर्शन करके ही अध्यक्ष को राजी करते हैं। और जैसा कि मैंने बुधवार को संकेत दिया था, अध्यक्ष के फैसले से सम्मान पैदा होना चाहिए न कि चुनौती। सदन के महत्व और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर जोर देते हुए सभापति ने कहा, यह सदन सिर्फ बहस के सदन से कहीं अधिक है। हमारी राष्ट्रीय भावना यहीं से गूंजनी है। संसदीय व्यवधान कोई उपाय नहीं है, यह एक राग है, यह हमारी नींव को कमजोर करता है... हमें आपकी प्रासंगिकता बरकरार रखनी चाहिए।

उन्होंने सांसदों से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अर्थ संवाद में शामिल होने का भी आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि माननीय सदस्यों, जब हम इस प्रकार के आचरण में संलग्न होते हैं, तो हम संवैधानिक नियमों से भटक जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं। राष्ट्रवाद को पोषित करना हमारा कर्तव्य है। मैं आप सभी से सार्थक संवाद की भावना को अपनाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें संविधान की भावना का अपमान नहीं करना चाहिए।

इसके तत्काल बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नोटिस खारिज किए जाने के बाद व्यवस्था का प्रश्न

उठाया और अदाणी मुद्दे पर चर्चा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सभापति धनखड़ ने तिवारी से कहा कि उनकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। प्रमोद तिवारी ने चेयरमैन की ओर इशारा करते हुए कहा कि सर आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस पर जगदीप धनखड़ ने टोकते हुए कहा कि यह बात आप जयराम रमेश को भी बताइए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं वह सहमति देने के लिए तत्पर हूं। मगर कुछ नियम हैं।

लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने अदाणी समूह से जुड़े मामले तथा उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही, सदन ने वक्फ (संशोधन) विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में हंगामे को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी ने मिलकर फैसला किया था कि कौन सा विधेयक आएगा और कब आएगा...जो बाकी मुद्दे हैं उन पर चर्चा का अलग अलग नियम बना हुआ है।

उद्धव ठाकरे के खिलाफ भाजपा ने बना ली तगड़ी रणनीति

■ एकनाथ शिंदे के लिए अभी असली उड़ान बाकी है

मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब सब की निगाहें बीएमसी चुनाव पर है। भारत की सबसे अमीर नागरिक निकायों में से एक पर शिवसेना का लंबे समय से कब्जा रहा है। हालांकि अब शिवसेना विभाजित हो गई है जिसके बाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली लड़ाई देखने को मिलेगी। बीएमसी का 5 साल का कार्यकाल 2022 में ही समाप्त हो चुका है। लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाए।

बीएमसी के नगर आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे ही महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होगा, उसके तुरंत बाद बीएमसी का चुनाव कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बीएमसी चुनाव में मजबूत करने की कोशिश करेगी। भाजपा को यह भी अच्छे से पता है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो शिवसेना कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनके प्रति और ज्यादा होगी और बीएमसी चुनाव में इसका फायदा भी हो सकता है।

अगर बीएमसी चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना सफलता पाने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। इससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर होगी बल्कि भविष्य पर भी ग्रहण लग सकता है। यही कारण है कि अभी भाजपा एकनाथ शिंदे को लेकर और आगे बढ़ाने की कोशिश में है। बीएमसी चुनाव कोविड-19 महामारी और ओबीसी सीटों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मामलों और पहले की परिसीमन प्रक्रिया के कारण नहीं हो सके। बीएमसी को सात जोन में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक में 3 से 5 वार्ड हैं।

कुल मिलाकर, मुंबई को 24 प्रशासनिक वार्डों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे 227 नागरिक चुनावी वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बीएमसी के चुनाव भारत के सबसे उत्सुकता से लड़े जाने वाले नागरिक निकाय चुनावों में से एक हैं। 2017 के बीएमसी चुनावों के बाद, शिवसेना 84 सीटों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद बीजेपी (82), कांग्रेस (31), एनसीपी (9), एमएनएस (7) और अन्य (14) हैं।

पिछले 25 सालों से मुंबई में सेना-बीजेपी गठबंधन लगातार सत्ता पर काबिज है. मुंबई, जिसमें मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के दो जिले हैं, में छह लोकसभा सीटें और 36 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनावों में, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 36 में से 22 सीटें जीतकर मुंबई पर अपना दबदबा बना लिया। महायुति के लिए, भाजपा ने 15 सीटें जीतीं, शिवसेना ने छह और राकांपा ने एक सीट जीती। जहां तक ??महा विकास अघाड़ी का सवाल है, शिवसेना (यूबीटी) ने 10 सीटें और कांग्रेस ने तीन सीटें जीतीं। समाजवादी पार्टी (सपा) ने एक जीत हासिल की।

बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, बोलीं-

'इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़ी हूं'

कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) के भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों पर भारतीय नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर केंद्र के साथ खड़ी है।

विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचे। मैंने यहां इस्कॉन से बात की है। चूंकि यह दूसरे देश से जुड़ा मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं। इससे पहले बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने हमलों की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंसा की निंदा करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कट्टरपंथियों के चंगुल में बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए कहा, हिंदुओं पर हमले और धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी अमानवीय और अस्वीकार्य है। उन्होंने विपक्षी नेताओं की इस मुद्दे को नज़रअंदाज़ करने के लिए आलोचना की और सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। सोमवार को बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के हज़रत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इस्कॉन के भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ़्तार किया।

बिहार विधानसभा में बैठने को लेकर हंगामा

पटना। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब विपक्ष के एक विधायक ने मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित सीट पर बैठने की धमकी दी, जिससे आसन पर हंगामा मच गया। इस घटना के बाद स्पीकर नंद किशोर यादव ने मार्शलों को बुलाया और आरजेडी विधायक को बाहर निकालने की चेतावनी दी, इसके बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रश्नकाल के बाद सीएम नीतीश कुमार के सदन से बाहर जाने पर हंगामा शुरू हुआ। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता अपनी कुर्सी पर खड़े होकर अपनी पार्टी के बागी विधायकों के सत्ता पक्ष की सीटों पर कब्जा करने पर आपत्ति जताने लगे। मेहता ने कहा, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लोग अपनी मर्जी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो इससे अव्यवस्था पैदा होगी।

इस बीच आरजेडी, कांग्रेस और तीन वामपंथी दलों के अन्य विपक्षी विधायक भी नारेबाजी करते हुए सदन के सामने आ गए। स्पीकर इस शोरगुल से हैरान रह गए और उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि जब तक वे अपनी सीट पर वापस नहीं चले जाते, तब तक उनकी कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी।

खेल
प्रमुख समाचार

एडिलेड से पहले कैनबरा पहुंची टीम इंडिया

कैनबरा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला एडिलेड में पिंक बॉल से खेला जाना है। पर्थ टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया हालांकि एडिलेड से पहले कैनबरा पहुंची है। बीसीसीआई ने इसका वीडियो एक्स पर शेयर किया। वीडियो में कप्तान रोहित शर्मा समेत टीम के अन्य खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस दौरान वीडियो में विराट कोहली, शुभमन गिल और आर अश्विन नजर नहीं आए।

एडिलेड से पहले टीम इंडिया के कैनबरा पहुंचने का कारण पिंक बॉल प्रैक्टिस मैच है, जो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर इलेवन टीम के खिलाफ खेलना है। बता दें कि, टीम इंडिया को पिंक बॉल के साथ एडजस्ट कराने के लिए एक वॉर्म अप मैच है, ऐसे में भारत 11 नहीं बल्कि परे स्क्वॉड के साथ खेल सकता है। इसमें हर बल्लेबाज को बैटिंग और हर गेंदबाज को बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, जिससे टीम एडिलेड टेस्ट की तैयारी करेगी।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 6 दिसंबर से खेला जाना है। भारत पिछली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पिंक बॉल टेस्ट में 36 रन पर ढेर हुआ था, लेकिन फिर भी टीम सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब रही थी। अगर इस बार टीम इस पिंक बॉल टेस्ट की परीक्षा पार कर लेती है तो वह सीरीज में 2-0 की तो बढ़त बनाएगी ही उनके सीरीज जीतने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1,190 अंक फिसला निफ्टी 24,000 के नीचे बंद

नईदिल्ली। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी50 में जोरदार गिरावट देखने को मिली। यह गिरावट ग्लोबल मार्केट में कमजोरी और मासिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सपायरी के दबाव के कारण आई। बीएसई सेंसेक्स 1,190 अंक या 1.48% टूटकर 79,043.74 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 80,447.40 के हाई और 78,918.92 के लो को छुआ। एनएसई निफ्टी50 भी 360.75 अंक या 1.49% गिरकर 23,914.15 पर बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी ने 24,345.75 के हाई और 23,873.35 के निचले स्तर पर कारोबार किया। निफ्टी50 के 50 में से 46 शेयर लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में एसबीआई लाइफ, इंफोसिस, एचडीएफसी लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अदाणी पोर्ट्स शामिल रहे, जिनमें गिरावट 5.41 प्रतिशत तक रही।

परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण

नईदिल्ली। आईएनएस अरिघाट से परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत ने हाल ही में कमीशन की गई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से परमाणु-सक्षम पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) का परीक्षण किया है, जिसे 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। सूत्रों ने बताया कि विशाखापत्तनम के तट पर हुए इस परीक्षण में के-4 मिसाइल शामिल थी, जो एक ठोस ईंधन वाली एसएलबीएम है। अगस्त में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए आईएनएस अरिघाट से के-4 मिसाइल का यह पहला परीक्षण था। पिछले कई वर्षों में के-4 का परीक्षण अब तक केवल सबमर्सिबल पोंटून से ही किया गया है।

एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने कमर्शियल पावर सप्लाई शुरू की

नईदिल्ली। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की इकाई एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने मध्य प्रदेश में शाजापुर सौर परियोजना में 55 मेगावाट के पहले हिस्से से बिजली की वाणिज्यिक आपूर्ति शुरू कर दी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) की 105 मेगावाट की शाजापुर सौर परियोजना (इकाई-I) में से 55 मेगावाट के पहले हिस्से के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत 29 नवंबर 2024 देर रात 12 बजे से हो गई। एनटीपीसी ने शेयर बाजार को अलग से दी सूचना में बताया कि एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित तथा वाणिज्यिक क्षमता अब 76530.68 मेगावाट हो गई है।

अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया ने 100 करोड़ रुपये कर्ज चुकाया

नईदिल्ली। अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड ने कॉरपोरेट ऋण में से 100 करोड़ रुपये चुका दिए हैं और अब बकाया ऋण घटकर 693 करोड़ रुपये रह गया है। मुंबई स्थित कंपनी में शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने '' अपने कॉर्पोरेट ऋण में से 100 करोड़ रुपये चुका दिए हैं। यह पुनर्भुगतान 225 करोड़ रुपये की हालिया इक्विटी पेशकश के जरिये जुटाई गई धनराशि से किया गया।'' कंपनी सूचना के अनुसार, '' बकाया ऋण 793 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के अनुसार) से घटकर 693 करोड़ रुपये हो गया है।'' अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के निदेशक धवल अजमेरा ने कहा कि कॉर्पोरेट ऋण को कम करने की खुशी हैज्कंपनी पांच गुना वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम उस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है।

'रेवड़ी कल्चर' से अर्थव्यवस्था के पतन का खतरा

के.एस. तोमर

महाराष्ट्र में 'इंडिया' गठबंधन को हराने में महायुक्ति की बात करने से पहले, विशेषकर भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा किए बिना, यह महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर 2.5 करोड़ वोटों को हासिल करने के लिए 1500 से 2000 रुपए प्रति माह की नकद सहायता जैसे मुफ्त तोहफों के परिणामों का विश्लेषण करें, जिससे राज्य के वित्त पर वार्षिक 63,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पडने का अनुमान है, जो भविष्य में राज्य की वित्तीय स्थिति को आर्थिक संकट में डाल सकता है।

महाराष्ट्र में चुनावी वादों को लागू करने की कुल लागत 1.55 लाख करोड़ रुपए से 1.70 लाख करोड़ रुपए तक वार्षिक हो सकती है, जबकि झामुमो और कांग्रेस गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र के लिए

49,550 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्चा हो सकता है। 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन योजना', जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह का नकद ट्रांसफर करना है, इसका वार्षिक खर्च 12,000 करोड़ रुपए हो सकता है। महायुक्ति के मामले को महाराष्ट्र में अलग-थलग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 'इंडिया' गठबंधन ने चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा महिलाओं और अन्य योजना लाभार्थियों को दी गई योजनाओं का लाभ उठाया था ताकि सत्ता की पुनः स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

18-50 वर्ष की आयु की गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए का 'डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर' चुनाव में लाभकारी साबित हुआ। इसी तरह, 40 लाख परिवारों के 3,500 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए गए और एक सार्वभौमिक पैंशन योजना के तहत 40 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रदान किए गए। आलोचक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 'रेवड़ी कल्चर' पर कड़ी आलोचना की थी क्योंकि इससे देश अंधकार की ओर बढ़ सकता था। लेकिन भाजपा ने महिलाओं को नकद ट्रांसफर को सशक्तिकरण का नाम दिया है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा किए गए समान कल्याण उपायों के खिलाफ है। वास्तविकता यह है कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट में है और हिमाचल सरकार कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैंशन देने की अनिवार्य व्यवस्था का पालन करने में भी असमर्थ है। भाजपा पर यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है, 'अगर आप करो तो पाप है, मगर मैं करूं तो पुण्य है।'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्पष्ट आकलन सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में 'लाडकी बहन योजना' को वित्तीय प्रतिक्रिया की इक्षचता के कारण अस्वीकृत कर दिया, जिससे अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर असर पड़ता। मध्य प्रदेश की तरह, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र चुनावों में महायुक्ति के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई, लेकिन इसके परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डालेंगे और यह हर राजनीतिक पार्टी को देशभर में आगामी विधानसभा चुनावों में ऐसे मुफ्त उपहारों की घोषणा करने के लिए प्रेरित करेगा। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में इन वायदों को लागू करने की कुल लागत 1.55 लाख करोड़ रुपए से 1.70 लाख करोड़ रुपए वार्षिक हो सकती है, जिसमें सड़क निर्माण और 'विजन महाराष्ट्र 2029' जैसी एकमुश्त आधारभूत परियोजनाओं का खर्च शामिल नहीं है। सरकार को महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उधारी में वृद्धि, धन का पुनः आबंटन, या नए राजस्व सृजन रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है। इन वायदों को वित्तीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना वास्तविक चुनौती होगी।

झारखंड में स्थिति भी उतनी ही चिंताजनक है। जे.एम.एम.(झामुमो) और कांग्रेस गठबंधन के घोषणा पत्र जनता की भावनाओं को लुभाने के लिए किए गए चुनावी वायदों का प्रतीक हैं, खासकर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच। जे.एम.एम. के वायदों में व्यापक लाभ शामिल हैं, जो रोजगार सृजन से लेकर सबसिडी वाली आवश्यक वस्तुओं तक हैं, जिनके वित्तीय प्रभाव बड़े होंगे।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल श्री डेका ने कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास का किया निरीक्षण

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान गुरुवार को गंगानगर बस्ती क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित आवास का निरीक्षण किया और हितग्राही श्रीमती कुमारी श्रीवास से बातचीत कर जानकारी ली। श्री डेका ने हितग्राही को श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया।

राज्यपाल श्री डेका ने बैगा हितग्राही का किया सम्मान

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री जनमन योजना के हितग्राही श्री बुधे लाल बैगा से मुलाकात की और उन्हें श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। यह हितग्राही जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्राम सिंघनपुरी हाथी डोब (धन डबरा) का निवासी है। इस अवसर पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा मौजूद थे।

डॉ.सहारे का निलंबन रद्द, कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन पद पर किये गये बहाल

रायपुर। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद

छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सिम्स के पूर्व डीन डॉ. के के सहारे के निलंबन को रद्द करते हुए उन्हे कोरबा मेडिकल कॉलेज में डीन के पद पर बहाल किया गया। उनकी बहाली का आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक अनियमितताओं और अन्य आरोपों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 23 सितंबर को डॉ. सहारे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ डॉ. सहारे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 21 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉ. सहारे को राहत दी और उनके निलंबन पर रोक लगा दी थी।

सुबोध हरितवाल से हुए विवाद पर राजेश पांडे से मांगा गया जवाब

बिलासपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में बुधवार को कांग्रेस की बैठक में जिला प्रभारी महामंत्री सुबोध हरितवाल और कांग्रेस नेता राजेश पांडे के बीच विवाद हो गया था। अब मामले में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजेश पांडे से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि बुधवार को बिलासपुर के कांग्रेस भवन में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संबंध में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए थे। बैठक पूर्व मेयर राजेश पांडे को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद राजेश पांडे और सुबोध हरितवाल के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराई थी।

इवेंट कंपनी के दफ्तर से लैपटाप व डेस्कटाप चुराने वाले तीन चोर गिरफ्तार

रायपुर। लोधीपारा स्थित जीटी प्लाजा के प्रथम तल में स्थत इवेंट कंपनी के दफ्तर से एक नग लैपटॉप व डेस्कटॉप चोरी करने वाले तीन चोरों को पंडरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने नगद 65 हजार रुपये भी जप्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रीनडले विहार के पास तिवारी हाउस मोवा निवासी कमलेश सातनकर ने पंडरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हैं। उसका आफिस जीटी प्लाजा के प्रथम तल पर 19 लोधीपारा रायपुर में स्थित है। सोमवार को दोपहर करीबन 12.00 बजे कमलेश के स्टाफ राजेश वर्मा ने दुकान में ताला बंद कर चाबी को गार्ड रूम में रखकर चला गया था। मंगलवार को सुबह करीब 10.45 बजे कमलेश के पडोसी दुकानदार ने फोन से सूचना दी कि दुकान का चाबी ताला में लगा और शटर खुला हुआ है। कमलेश आकर दुकान अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ था। और नग लैपटाप एवं एक डेस्कटाप नहीं था। कोई चोरी कर ले गया था। इस रिपोर्ट पर पंडरी पुलिस ने में धारा 331(4), 305, 3 (5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज पड़ताल शुरू किया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही कांप्लेक्स में लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजों को देखने पर 3 युवकों को चोरी करते देखा गया। युवकों की पहचान खपराभी लोधीपारा चौक पंडरी निवासी कृष्णा ललित कुमार प्रजापति, युवराज वर्मा एवं तुषार भट्ट उर्फ सागर के रूप में किया गया और गिरफ्तार कर थाने लगाया गया।

विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु 03 दिसम्बर को होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन

अम्बिकापुर। उपसंचालक रोजगार ने बताया कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र अम्बिकापुर के द्वारा 03 दिसम्बर 2024 को प्रात: 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। जिसमें निजी नियोजक एन.जे. ग्रुप पता प्रथम तल तिरुपति बालाजी बिल्डींग भाटागांव के पास रायपुर के एम.डी. सुश्री एन. निर्मला उपस्थित रहेंगी। जिसके अंतर्गत सेल्स मार्केटिंग के 300 पद, असेम्बली (मोब) के 200 पद, एसोसिएट के 100 पद एवं सीएनसी ऑपरेटर के 200 पदों पर भर्ती की जानी है।

जनजातीय संस्कृति ने भगवान श्रीराम को अपने हृदय में बसा रखा है: साय

मुख्यमंत्री ने जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित

रायपुर। जनजातीय समाज का इतिहास धरती पर मनुष्य के पहले पदचाप के साथ जुड़ा हुआ है। जनजातीय संस्कृति ने भगवान श्रीराम को अपने हृदय में बसा रखा है। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में ही वनवास बिताया, यहीं पर उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाए। जनजातीय अस्मिता का प्रश्न भारत की सनातन परंपरा की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमें जनजातीय समुदायों की अस्मिता और विरासत के प्रति संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व मिला है। आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मु भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजाति समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज है। यह समाज कुप्रथाओं का मुखर विरोध करता है। भारत की संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जनजातीय जननायकों के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी की पहल पर पूरे देश में 13 से 15 नवम्बर तक जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की परंपराओं, संस्कृति रीति-रिवाज, तीज-त्यौहार और शासन द्वारा जनजातीय उत्थान के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की।

साय ने कहा कि 13 नवंबर को जशपुर जिले में आयोजित पदयात्रा इतनी सफल रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी खुलकर तारीफ की और ऐसे आयोजनों को जनजातीय समाज के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हुए राष्ट्रीय आयोजन ने अन्य प्रांतों से आए आदिवासी समुदाय को एक दूसरे की संस्कृति को जानने-समझने का सुंदर अवसर दिया। साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल ने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे पहले पृथक जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाया और आदिवासियों के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी।

उन्होंने कहा कि हम मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों में अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए अपनी योजनाएं और नीतियां बना रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक समुदाय के पास विकास के समान अवसर हों और जनजातीय समाज अपनी प्राकृतिक और भौगोलिक जटिलताओं पर जीत हासिल करते हुए समग्र भारत के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। जब हम जनजातीय समुदायों की अस्मिता की रक्षा करेंगे, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करेंगे, उनके इतिहास और उनके नायकों का गौरवगान करेंगे तो निश्चित रूप से मां भारती का यश बढ़ेगा, उसका गौरव गान होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत के जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए मोदी जी पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं चला रहे हैं। ये योजनाएं जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी योजनाएं साबित हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी अनेक योजनाओं से जनजातीय समुदायों को बड़ा संबल मिला है। पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर अंचल में शांति स्थापित करने के लिए तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से शासन की योजनाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने की अनूठी पहल की गई है। बस्तर अंचल में सुरक्षाबलों के 34 नए कैंप खोले गए हैं और लगभग 96 गांवों में शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जनजातीय महानायकों के गौरवशाली इतिहास की जानकारी आने वाली पीढ़ी को हो इसलिए ऐसे आयोजन आवश्यक हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके मूल्यों को अगली पीढ़ी तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने सदैव प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कार्य किया है।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता अतुल जोग ने कहा कि बिना स्वार्थ के जनजातीय समाज ने मानव सेवा का काम किया है। इसका सुंदर उदाहरण पद्म पुरस्कारों की घोषणाओं में भी देखने को भी मिला, जिसमें बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग शामिल रहे हैं। संगोष्ठी को पवन साय और अनुराग जैन ने भी संबोधित किया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

रायपुर दक्षिण से नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने ली पद की शपथ

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में रायपुर दक्षिण उपचुनाव में नव निर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित मंत्रीगणों और विधायकों ने सोनी को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। विधायक सुनील सोनी की प्रचंड जीत पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सुनील सोनी की आवाज मजबूत रहेगी और वह क्षेत्र की जनता के हित में काम करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ी राजभाषा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। प्राइमरी शिक्षा में इसे महत्व दिया जा रहा है और सरकारी कार्यों में इसके उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा कि, डॉ सिंह ने कहा कि शीतकालीन सत्र में

प्रदेश की जो मुख्य समस्याएं है उनका निराकरण होगा, इसके लिए सरकार की तैयारी भी पूरी है। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की है, पार्टी का कहना है कि 16 से 20 दिसंबर तक किया गया है। सत्रावधि के मध्य में 18 दिसंबर को बाबा गुरूघासीदास की जयंती है, जिसके मद्देनजर व्यापक कार्यक्रमों की दृष्टि से प्रदेश के अधिकतर विधानसभा सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित होने में असुविधा होगी। कांग्रेस की शीतकालीन सत्र की तारीख बदलने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 4 दिन का सत्र होने वाला है और 18 दिसंबर को छुट्टी है।

कांग्रेस अपनी नीति के कारण खोती जा रही है जनता का विश्वास: मुख्यमंत्री

■ **कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक पर गरमाई सियासत**

रायपुर। बिलासपुर कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक के बाद पूर्व मेयर राजेश पांडे और कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल के बीच हुई तीखी नोकझोक के बाद अब सियासी पारा हाई हो गया है। इस घटना पर सीएम विष्णुदेव साय समेत बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस अपनी नीति के कारण देश और प्रदेश की जनता का विश्वास खोती जा रही है। आगे कुछ दिन देखिए यह लोग नजर नहीं आएंगे। रायपुर दक्षिण में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कांग्रेस को जितना वोट नहीं जुटा मिला, उससे ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती है।

वन मंत्री कश्यप ने दी प्रतिक्रिया

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं पर

कंट्रोल नहीं है। यह स्पष्ट दिखता है। पीसीसी अध्यक्ष के कार्यक्रम में इस तरह की घटना हो रही है। अभी तो निचले स्तर पर हुआ है। आने वाले समय में उच्च स्तर पर हो रही ऐसी घटनाएं सामने आएंगी।

विधायक धरमलाल लाल कौशिक का बयान

बीजेपी के वरिष्ठ नेता धरमलाल कौशिक ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। कांग्रेस नेता जब लड़ते-झगड़ते हैं, तभी पता चलता है कि उनकी बैठक हो रही है। हमारी शुभकामना है इस तरह की बैठक करते रहें। प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में यह स्थिति निर्मित होना इस बात को साबित करता है। कांग्रेसी अपने प्रदेश अध्यक्ष की कितनी इज्जत करते हैं। वे इस तरह के जितनी बैठक करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। कांग्रेसियों के लिए यह सामान्य घटना है।

बता दें कि बुधवार को बिलासपुर के कांग्रेस भवन में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संबंध में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए थे। इसी बैठक पूर्व मेयर राजेश पांडे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। जिसके बाद राजेश पांडे और सुबोध हरितवाल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं बैठक में उपस्थित कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने हस्तक्षेप कर दोनों नेताओं के बीच सुलह कराई।

आत्मसमर्पित नक्सलियों व नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास: उपमुख्यमंत्री शर्मा

■ **भारत सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा समय समय पर अपने दौरे के दौरान आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से

मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोडने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।

इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस का प्रदेशवासियों को दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाखा म हमर माटी के महक आथे। छत्तीसगढ़ी भाखा हमर अभिमान ए। सब अपन भाखा ला मान देहू तभे वो आघू बढ़ही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ी को दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार-प्रसार की भाषा बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ उनका परिचय नई पीढ़ी से कराना भी जरूरी है।

छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को राजभाषा दिवस के रूप में मनाने की वजह यह है कि 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक के पास होने के बाद

ही हर साल 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन छत्तीसगढ़ी के प्रचलन, विकास, और राजकाज में इस्तेमाल के लिए किया गया था। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की पहली कार्यकारी बैठक 14 अगस्त, 2008 को हुई थी। इस दिन को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का %कार्यालय स्थापना दिवस% के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले सचिव पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे थे। छत्तीसगढ़ी को दक्षिण कोसली और कोसली भी कहा जाता है। आस-पास के पहाड़ी लोग छत्तीसगढ़ी को खालताही कहते हैं। ओडिशा से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले लोग छत्तीसगढ़ी को लारिया कहते हैं।

देश के दस प्रमुख लेखकों में गिरीश पंकज का नाम

■ **मुख्यमंत्री साय ने भी बधाई दी**

रायपुर। दो दिन पूर्व राही रैंकिंग ने देश के सौ महत्वपूर्ण लेखकों की सूची जारी की है, उसमें दस शीर्ष लेखकों में गिरीश पंकज का नाम शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी और फेसबुक में भी लिखा कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री गिरीश पंकज को राही संस्थान द्वारा देश के 100 बड़े साहित्यकारों की सूची में 10वें स्थान में शामिल किया जाना, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। हिंदी भाषा की सेवा में तल्लीन गिरीश जी पिछले 40 वर्षों में 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं और अनेक

पुरस्कारों से सम्मानित हैं।इस उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मंत्री श्री रामविचार नेताम और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (सांसद कोरबा) इत्यादि ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी। इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गिरीश पंकज ने कहा कि संभवत: यह पहली बार हुआ है, सत्ता में बैठे महानुभावों ने किसी लेखक के प्रति ऐसी सद्भावना दिखाई। यह बहुत अच्छा संकेत है। मेरे प्रति असंख्य के लोगों ने कल सद्भावना दिखाई, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि सम्मान आते-जाते रहेंगे, क्रम बदलते भी रहेंगे, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें निरंतर श्रेष्ठ साहित्य का सृजन करना है। समाज को किसी लेखक का केवल और केवल सृजन ही याद रहता है।

इस उपलब्धि के लिए हरिजन सेवक संघ के सचिव पन्नालाल नवरंगे एवं अन्य सदस्यों ने गांधी आश्रम परिसर में गिरीश पंकज का गांधी प्रतिमा के सामने शॉल, श्रीफल और

इवेंट कंपनी के दफ्तर से लैपटाप व डेस्कटाप चुराने वाले 3 गिरफ्तार

रायपुर। लोधीपारा स्थित जीटी प्लाजा के प्रथम तल में स्थत इवेंट कंपनी के दफ्तर से एक नग लैपटॉप व डेस्कटॉप चोरी करने वाले तीन चोरों को पंडरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने नगद 65 हजार रुपये भी जप्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रीनडले विहार के पास तिवारी हाउस मोवा निवासी कमलेश सातनकर ने पंडरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हैं। उसका आफिस जीटी प्लाजा के प्रथम तल पर 19 लोधीपारा रायपुर में स्थित है। सोमवार को दोपहर करीबन 12.00 बजे कमलेश के स्टाफ राजेश वर्मा ने दुकान में ताला बंद कर चाबी को गार्ड रूम में रखकर चला गया था।

मंगलवार को सुबह करीब 10.45 बजे कमलेश के पडोसी दुकानदार ने फोन से सूचना दी कि दुकान का चाबी ताला में लगा और शटर खुला हुआ है। कमलेश आकर दुकान अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ था। और नग लैपटाप एवं एक डेस्कटाप नहीं था। कोई चोरी कर ले गया था। इस रिपोर्ट पर पंडरी पुलिस ने में धारा 331(4), 305, 3 (5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज पड़ताल शुरू किया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही कांप्लेक्स में लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजों को देखने पर 3 युवकों को चोरी करते देखा गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.